सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-34 अंक-17 | 7 से 21 सितम्बर, 2019 | मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

देश में वैज्ञानिक, तर्कशील चिंतन को खत्म कर देना चाहती है भाजपा

— कॉमरेड प्रभास घोष

5 अगस्त को महान मार्क्सवादी विचारक कॉमरेड शिवदास घोष के स्मरण दिवस पर कोलकाता के नेताजी इन्डोर स्टेडियम में पार्टी के महासचिव कामरेड प्रभास घोष का भाषण हुआ। उन्होंने प्रकाशित करने से पहले भाषण को संपादित किया। मूल रूप से बंगाली में दिये गए इस भाषण का हिन्दी रूपान्तर हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं।

कॉमरेड अध्यक्ष और कामरेडो,

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आज का यह दिन हम सभी के जीवन में एक गहरी व्यथा-वेदना, भावनाओं और यादों से भरा दिन है। आप जानते हैं, हमारा कोई भी कार्यक्रम सिर्फ औपचारिक नहीं होता है। आज का यह कार्यक्रम भी नहीं है। कुछ शोक, दुःख समय के साथ हल्के पड़ जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। फिर, एक शोक ऐसा होता है जो जैसे-जैसे दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, और इस घटना के घात-प्रतिघात में, चेतना की गहराई और समझदारी में ऐसी अपील पीछे छोड़ जाते हैं जो बार-बार विवेक को, कर्तव्य की भावना को झकझोर देती है, जगाती रहती है।

आज पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। यह स्मरण सभा भारत के 23 राज्यों में आयोजित की जा रही है। पार्टी में अब मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान परिवारों के बहुत सारे युवक-युवतियां शामिल हो रहे हैं। उनमें से बहुत से लोगों को अच्छी तरह से पता नहीं है कि किन कठिन और कठोर संघर्षो के माध्यम से महान मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन- स्टालिन-माओ त्से-तुंग के सुयोग्य उत्तराधिकारी कॉमरेड शिवदास घोष ने केवल छह साथियों को लेकर इस पार्टी को बनाना शुरू किया था। मैं इस बारे में बाद में चर्चा करूंगा।

वेद-वेदांत-कुरान-बाइबिल से नहीं आया संसदीय लोकतंत्र

इस सभा में,सबसे पहले, मैं आपको हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों और उसके परिणामों पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष के विचारों के आधार पर पार्टी के विश्लेषण को प्रस्तुत करूँगा। पहले ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि संसदीय लोकतंत्र हमेशा इतिहास में नहीं था, यह वेद-वेदांत, कुरान, बाइबिल की वाणी से नहीं आया था। संसद, संसदीय लोकतंत्र, व्यक्ति-स्वाधीनता, विरोध करने का व्यक्ति का अधिकार, आन्दोलन करने का अधिकार, धार्मिक प्रभाव से मुक्त मानवतावाद, वैज्ञानिक तर्कशीलता, लोकतांत्रिक समाज, स्वतंत्रता-समानता और भाईचारे का पैगाम

कोलकाता, 5 अगस्त : नेताजी इंडोर स्टेडियम में कॉ. शिवदास घोष स्मृति सभा को संबोधित करते हुए कामरेड प्रभास घोष

आदि के ऐलान के साथ लोकतांत्रिक क्रांति मानव इतिहास में राजशाही के खिलाफ रक्तरंजित लड़ाई के जरिए एक दिन आई थी। वाणिज्यिक पूंजी के गर्भ से उत्पन्न औद्योगिक पूंजी उन दिनों लघु उद्योग-कुटीर उद्योग के स्तर पर थी। इस नवजात औद्योगिक पूंजी को विकसित करने के हित में, उन दिनों पूंजीवाद के किशोर-युवा अवस्था के स्तर पर, उसके साथ धर्म-आधारित राजतंत्र का जो संघर्ष पैदा हुआ, उस दौर में प्रगतिशील पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में ग्रामीण भूदासों से सामंती गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के लिए आह्वान किया गया। धार्मिक शासन वाले राजतंत्र का खात्मा करके प्रजातंत्र कायम हुआ। यह निर्धारित किया जाता है कि शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बने एक संविधान द्वारा शासित होगा, न कि किसी धार्मिक अनुशासन द्वारा, जिसमें बाहुबल भी शामिल है। छोटे उद्योग में स्वतंत्र और बेरोकटोक प्रतिस्पर्धा थी, जिससे बहु-उद्योग के आधार पर बहु-पार्टी या बहुदलीय लोकतंत्र आया था। उनकी घोषणा थी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का (बाई द पिपल, ऑफ द पिपल, फॉर द पिपल, स्वतंत्रता- समानता-बंधुता था। यद्यपि यह घोषणा प्रारंभिक वर्षों में थोड़ी रक्षा कर सकी थी, पूंजीवाद के विकास के एक चरण में पहुंचकर जब छोटी पूंजी बड़ी पूंजी में तब्दील हो गई, बड़ी पूंजी एकाधिकार पूंजी बन गई, प्रगति के झण्डे को फेंक कर प्रतिक्रियावादी हो गई, तब से ही स्वतंत्रता-समानता-बंधुता का पैगाम ताक पर रख दिया जाने लगा। लोकतंत्र भूलुण्ठित होने लगा। संसदीय लोकतंत्र का राग अलापने की आड़ में एकाधिकार पूंजी और साम्राज्यवादी स्तर पर पहुंच चुके पूंजीवादी देशों ने न केवल अपने ही देश के श्रमिकों का शोषण किया, बल्कि पिछड़े देशों को पैरों तले रौंदते हुए औपनिवेशिक- अर्द्धऔपनिवेशिक शोषण-लूट मचाई, आजादी आन्दोलन का दमन करने के लिए नृशंस अत्याचार किये, दो-दो बार विश्वयुद्ध की आग में धकेला। सन् 1917 में इस एकाधिकार पूंजी के स्तर में, साम्राज्यवादी पूंजी के स्तर में चुनाव के बारे में महान लेनिन ने कहा था, "बुर्जुआ संसदीय प्रणाली का वास्तविक चरित्र है आने वाले पांच साल के लिए शासक वर्ग का ताबेदार बन कर कौन सदस्य संसद के माध्यम से लोगों पर शोषण-उत्पीड़न करेगा, यह निर्धारित करना।" कॉमरेड शिवदास घोष ने 1969 में कहा था, "चुनाव एक बुर्जुआ राजनीति है। अगर लोगों की राजनीतिक चेतना न रहे, कोई मजदूर वर्ग का संघर्ष नहीं हो और वर्ग संगठन नहीं हो, अगर कोई जन आंदोलन नहीं हो, तो लोगों की कोई सचेत लामबंदी नहीं हो, तो उद्योगपति, बड़े-बड़े व्यापारी, प्रतिक्रियावादी लोग बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहा कर और मीडिया की मदद से जो हवा बनाते हैं, भोले-भाले लोग उनकी बहकावे में आकर इसमें बह जाते हैं।" वास्तव में, हमारे देश के चुनावों पर नजर डाल कर देखिए। चुनाव में कौन जीतेगा यह कौन तय करता है? क्या लोग तय करते हैं? चुनाव अभी भी वैसे ही हो रहे हैं। नतीजतन, लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए कहने को अब कुछ नहीं बचा है। अब है पूंजीपति वर्ग द्वारा, पूंजीपति वर्ग के लिए, पूंजीपति वर्ग का। पूंजीपति ही तय कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। नतीजतन, चुनाव परिणाम अब जनमत नहीं, बल्कि शोषक वर्ग का मत होता है। उनकी राय हीं सब कुछ तय कर रही है। अगर बाकी सभी सवालों को छोड़ भी दिया जाए, तो एक बात सोचने वाली यह है कि आपको संसदीय चुनाव में खड़े होने के लिए जमानत राशि के तौर पर 25,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। अगर आपको विधानसभा चुनाव में खड़ा होना है, तो आपको 10,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। क्या ऐसे में इस देश का कोई भी मजदूर -किसान- गरीब आदमी चुनाव में खड़े होने की सोच सकता है? वे ही तो बहुसंख्यक मतदाता हैं। इसके अलावा, करोड़ों गरीब लोग हैं जो दो जून रोटी के जुगाड़ के लिए सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं, जो रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं, जिनके पास शिक्षा-दीक्षा पाने का अवसर नहीं है, अगर सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक और एकजुट नहीं करे, उन्हें नैतिक रूप से ताकतवर नहीं करे, तो उनके पास राजनीति करने का मौका कहीं नहीं है। इसलिए वे यह मान लेते हैं कि राजनीति करना बड़े लोगों का, अमीरों काम है, गरीबों का नहीं। इसलिए वे बड़े पूंजीपतियों-व्यापारियों द्वारा दिए गए पैसों में अपना जमीर बेच देते हैं, भोले-भाले लोग उनकी बहकाई में आकर मीडिया द्वारा बनाई गई हवा में बह जाते हैं।

चुनाव का मतलब है पैसे का खेल

देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आज बेरोजगारों की यह फौज इस इन्तजार में बैठी रहती है कि कब चुनाव आए। जो पार्टी जितना ज्यादा पैसा देगी, वह बेरोजगार उसी पार्टी का बन कर काम करेगा। राजनीतिक पार्टियां चुनावों के समय पानी की तरह पैसा बहा कर, शराब पिला कर, मांस खिलाकर उनसे कोई भी घटिया कार्य करवा लेती हैं। एक बात और बहुत दुखदायक है। गरीब लोगों में एक विचार घर कर गया है कि उन्हें वैसे तो कुछ नहीं मिलेगाा, लेकिन वोट के दौरान उनको कुछ पैसे तो मिलेंगे। इस तरह, लोग अपने वोट को बेच देते हैं। इनके वोट खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं। जनता हमें बताती है कि आप चुनाव भला कैसे जीत सकते हैं? दूसरे लोग तो पैसा देते हैं, और आप हमसे ही पैसा लेते हैं और वोट भी मांगते हैं। आप पागल हैं। आपके लिए चुनाव जीतना संभव नहीं है। उनसे हमारा यह कहना है कि उस तरह हम चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको पैसा देने के लिए, हमें अपनी पार्टी को टाटा, अंबानी, अडानी को बेचना पड़ेगा। जिस तरह, उन पूंजीपतियों का काम करने के लिए चुनावी बॉन्ड में बीजेपी को 290 करोड़ रुपये मिले, कांग्रेस को 8 करोड़ रुपये और यहां तक कि सीपीआई (एम) को भी 2 करोड़ रुपये मिले। इन पार्टियों को कॉरपोरेट सेक्टर यानी धनकुबेरों के पैसों पर टिकाये रखना, उनकी जरूरत है। इस बार के चुनाव में क्या हुआ? पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, भाजपा ने लोगों से 'अच्छे दिन' लाने, काला धन वापस लाने, इसे बरामद करने और हर भारतीय के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपये डालने, हर साल 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करने, किसानों के कर्जे माफ करने, सामानों की कीमतों को कम करने, भ्रष्टाचार

(शेष पृष्ठ 2 पर)

असम में लाखों लोगों के नाम एनआरसी से हटाने के खिलाफ

5 सितंबर को देशव्यापी विरोध दिवस आयोजित करें – एसयूसीआई (सी)

केंद्र और असम राज्य सरकार द्वारा तथाकथित एनआरसी से 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर निकाले जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कामरेड प्रभास घोष ने 1 सितंबर, 2019 को निम्न बयान जारी किया:

घोर अंध-राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक ताकतों के इशारे पर भारत सरकार और असम सरकार द्वारा तथाकथित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की बदनियत योजना के तहत इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखे जाने पर हम गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। इनकी संख्या 19 लाख से अधिक है। समुदाय, जाति, भाषा और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का यह एक फासीवादी कदम है जो इन असहाय लोगों को पूरी तरह मौत और विनाश की ओर धकेल देगा। इसके अलावा यह शासक पूंजीपति वर्ग के हाथों को मजबूत करेगा ताकि वे जैसा चाहें लोगों में फूट डाल सकें और अपना दमनकारी शासन-शोषण जारी रख सकें।

अतः कामरेड घोष ने इन सभी 19 लाख लोगों के नाम तत्काल इसमें शामिल करने की पुरजोर मांग की है जो कई वर्षों से असम में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोगों से आह्वान किया कि वे इन सब के नाम असम के एनआरसी में शामिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मजबूर करने के लिए देशव्यापी शक्तिशाली संयुक्त आंदोलन विकसित करें। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि अन्य राज्यों में भी तथाकथित एनआरसी तैयार करने के इसी तरह के घोर फूटपरस्त कदम उठाने के आरएसएस-भाजपा सरकार के सुनियोजित कदम को नाकाम कर देने के लिए वे सभी आगे आएं।

कामरेड प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 1 का शेष)

पर अंकुश लगाने का वादा किया था। कहा था – 'न खाऊंगा, न ही खाने दूंगा' कांग्रेस के कुशासन से आजीज आकर, तंग होकर लोगों ने सोचा था कि शायद ये पार्टी कुछ करेगी। लेकिन यह सब एक जुमलेबाजी है, झांसा है खुद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष कह चुके कि 'चुनावी वादे जुमले हैं'। लोगों का संकट और विरोध बढ़ते-बढ़ते चरम पर पहुंच गया। उसका फायदा उठा कर कांग्रेस लगभग गुजरात चुनाव जीतने वाली थी, कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की, जिन राज्यों को लंबे समय से भाजपा के गढ़ के रूप में जाना जाता था। गोरखपुर में संसदीय उपचुनाव में भाजपा हार गई, यह देखकर कि विपक्षी खेमे ने मान लिया था कि इस बार विपक्ष जरूर जीत जाएगा। कयास लगाये जाने लगे कि कौन कितनी सीटों पर कब्जा करेगा, कौन सी सीट अपने हाथ में रखेगा-ये सभी सौदेबाजी अन्ततः चलने लगी, बहुत कुछ कालनेमी के लंका प्रायद्वीप के बंटवारे की तरह। कोई किसी को एक इंच भी जगह नहीं छोड़ेगा। बार-बार की बैठकों के बावजूद, राष्ट्रीय पूंजीवादी पार्टी और क्षेत्रीय पूंजीवादी पार्टियों के बीच महागठबंधन नहीं बन पाया और वह ध्वस्त हो गया। विरोधियों में से प्रधानमंत्री कौन होगा इस बात को लेकर 5-6 दावेदार सामने आ गए। इस बीच, चुनावों के असली नियंत्रणकर्ता बड़े पूंजीपतियों-बहुराष्ट्रीयों, बड़े व्यापारियों ने देखा कि इन पांच वर्षों में भाजपा ने उनकी जो सेवा की है, उसने कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दूसरे, फिलहाल सीटों को लेकर, प्रधानमंत्री पद को लेकर जब इतना द्वंद्व-संघर्ष, फूट है, असंतोष है, तब गठबंधन सरकार बनी तो स्थाई सरकार नहीं होगी, कलह और भी बढ़ेगी। परिणामस्वरूप, उन्होंने फैसला किया कि भाजपा को जिताना होगा। बीजेपी को जिताने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर इलेक्शन बॉन्ड का 95 प्रतिशत हिस्सा उसे देना पड़ेगा। भाजपा ने चुनाव पर 27,000 करोड़ रुपये खर्च किए। यह एक सार्वजनिक खाता है, इससे बाहर भी इसने अरबों रुपये खर्च किए। यह पैसा किसने दिया? ये सभी पैसे उन्हीं ने दिये थे जिनके लिए बीजेपी 'अच्छे दिन' लाई।

यह भाजपा के शासनकाल की एक तस्वीर है जो आप देखिए। भारत में एक प्रतिशत अमीरों के पास देश की 73 प्रतिशत धन-संपत्ति है। पिछले 2017-18 में, इन एक प्रतिशत अमीरों की धन-संपत्ति 20 हजार 913 करोड़ रुपये बढ़ गई है। नतीजतन, वे भाजपा को आशीर्वाद तो देंगे ही सिर्फ मुकेश अंबानी की दैनिक आय औसतन 300 करोड़ रुपये है। पिछले तीन वर्षों में, उनकी संपत्ति में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, गौतम अडानी की संपत्ति में 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि भगवा वस्त्रधारी रामदेव की आय में 173 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब, रामदेव हर चीज का कारोबार कर रहें हैं। इस समय के दौरान, बीजेपी के अध्यक्ष के अपने खुद के कारोबार की आय में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उनके बेटे की आय 1600 प्रतिशत बढ़ गई। उन्होंने बैंक से 1 लाख 56 हजार 702 करोड़ रुपये उधार लिए हैं, भाजपा सरकार ने उस ऋण को माफ कर दिया है। बैंकों के पैसों का मतलब है जनता का पैसा। टैक्स छूट की बाबत बड़े उद्योगपतियों को 13,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा दिये हैं। वे धड़ल्ले से भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। देश-विदेश में लाखों करोड़ रुपयों का अम्बार लगा रहे हैं। काला धन कौन जमा करते हैं? क्या छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी या ये बड़े-बड़े व्यापारी? परिणामस्वरूप, भाजपा सरकार एक भी रुपया काला धन बरामद नहीं कर पाई। काले धन के कारोबारी भी कहीं खोज नहीं पाई। वह कैसे खोज सकती है? वह सभी दोस्तों, नेताओं और मंत्रियों के आसपास ही घूम रहा है। वे ही तो फण्ड मुहैया करा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कभी कांग्रेस को भी दिया था।

बालाकोट को इस्तेमाल कर बनाई गई थी हवा

आपने इस बार के चुनाव में देखा है कि एक-दूसरे के खिलाफ क्या कीचड़ उछाला गया, कितनी भद्दी भाषा में एक-दूसरे पर क्या हमला किया गया, क्या जघन्य हमला किया, मां-बाप तक का नाम लेकर गालीगलौज किया। बुर्जुआ राजनेताओं ने गन्दी बात, हद दर्जे की अशालीनता की। वे मंत्री पद की हताशोन्मत लालसा में सब कुछ कर सकते हैं। इस स्थिति में, कांग्रेस ने भाजपा सरकार के राफेल युद्ध विमान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने खुद कबूल किया कि भारत के बीजेपी प्रधानमंत्री के अनुरोध पर अनिल अंबानी को युद्धक विमान बनाने का ठेका दिया गया था, जिनके पास जहाज बनाने का खुद का कोई कारखाना नहीं था। अखबार में यह बात लीक हो गई कि रक्षा विभाग के नौकरशाहों ने पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नौकरशाह सौदे की बातचीत में नियमों को ताक पर रख कर दखलअंदाजी कर रहे हैं। इसका सही-सही जवाब देने में नाकाम भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के बोफोर्स घोटाले को लेकर सवाल उठाया, जिस घोटाले को अभी भी दबा-छिपा कर रखा हुआ है। चूंकि अब चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए कांग्रेस अब राफेल की जांच को लेकर मुखर नहीं है। अगर चुनाव फिर से आया, तो शायद इस मुद्दे को फिर उठाएगी। दोनों पार्टियां एक-दूसरी के घोटाले के बारे में जानती हैं, इसे जरूरत पड़ने पर उठाती हैं और फिर दबा देती हैं। क्या कभी आपने सुना है कि भ्रष्टाचार के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों, मंत्रियों, नौकरशाहों को सजा हुई है? छोटे-छोटे चोर-उचक्कों को सजा दी जाती है। यही है मोदीजी का 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा'। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि विदेश जाने के लिए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या की मदद किसने की? इस स्थिति में, जब चुनाव की गर्मी बढ़ती है, तो लोग सोच रहे होते हैं कि 'क्या होगा', 'क्या होगा' अचानक कश्मीर के पुलवामा पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें कई सैनिक मारे गए, हालाँकि कश्मीर में पहले भी कई आतंकवादी हमले हुए हैं। सरकार ने ही कहा कि हमले में दो आतंकवादी मारने के लिए एक जवान खेत रहता है-मरने वालों की यही दर है। पुलवामा में घटी इस दुखद घटना को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना दिया। पलटवार के तौर पर पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमला किया गया। देशव्यापी प्रचार का एक तूफान उठाया गया कि प्रधानमंत्री कितना साहसी है, देशभक्त है और पाकिस्तान को जब्त कर लिया है। इससे पहले, कांग्रेस ने भी इसी तरह कारगिल युद्ध, बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के प्रसंग में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल किया था। अतः, भाजपा द्वारा अब बालाकोट को ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग करते हुए प्रचार माध्यमों से चुनाव में जोरशोर से हवाा बनाई गई।

कांग्रेस की राजनीति कुछ नहीं है अलग

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने भाजपा का तरफदार बनकर उसके लिए नग्न रूप से काम किया है। अब, चुनावों में भी हर तरह की धांधली-जालसाजी होती है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में धोखाधड़ी की जांच चल रही है। मतदान के अंतिम दौर में, प्रधानमंत्री एकदम भगवा वस्त्र धारण कर केदारनाथ में एक गुफा में ध्यानमग्न हो गए थे। इसी बीच, हिंदुओं के वोट पाने के लिए जो कुछ करना था, वह सब कुछ किया। हालांकि सीपीआई (एम) की 'धर्मनिरपेक्ष मित्र' कांग्रेस भी ऐसा करने में कम नहीं रही, भाजपा के साथ होड़ लगी कि पहले कौन मंदिर में पूजा करेगा, कहां किस देवता का आशीर्वाद लेंगे - यह सब किया। लेकिन केदारनाथ जाने की बात उनके दिमाग में नहीं आयी। वैसे, केदारनाथ पूंजीपति वर्ग ने तय कर लिया था कि इस बार भी वे भाजपा को ही गद्दी पर बिठाएंगे और बिठाया भी। इसलिए देखिए, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन दिखाई दिये? ये बड़े-बड़े पूँजीपति। यह उनकी जीत का जश्न था। याद रखें, अब कोई राजशाही नहीं है, लेकिन राजा है, लोकतंत्र के लबादे में पूंजीपति शासन करते हैं। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल उनके हुक्म पर चलने वाला उनका राजनीतिक प्रबंधक है।

इधर, डूबती नाव की तरह चुनावों में विपक्षी राष्ट्रीय बुर्जुआ पार्टी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय बुर्जुआ पार्टियों की स्थिति शोचनीय हो गई, भारी हताशा-निराशा हुई। जब भाजपा अतीत जैसे कांग्रेस अलोकप्रिय हुई थी, उसकी तरह बेहद अलोकप्रिय हो जाएगी, तब पूंजीपति वर्ग भविष्य के हित में इन दलों को फिर से खड़ा कर देगा, कांग्रेस को एक 'उद्धारकर्ता' के रूप में लोगों के सामने लाया जाएगा। बुर्जुआ द्विदलीय लोकतंत्र का ऐसा उलटफेर यूरोप में, अमेरिका में हो रहा है, इस देश में भी हो रहा है। सीपीआई(एम), सीपीआई की स्थिति भी घनघोर संकट में है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली अविभाजित सीपीआई (जिसमें सीपीआई(एम), सीपीआई, नक्सली सब शामिल थे) मुख्य विपक्षी दल बन कर उभरी थी। उन्होंने लंबे समय तक ऐसे 'वामपंथ' पर अमल किया है कि इस बार चुनाव में सीपीआई(एम) अपनी खुद के दम पर एक और डीएमके के कंधों पर चढ़ कर बाकी दो सीटें और सीपीआई को इसी तरह एक सीट मिली है। ऐसी ही दुर्दशा में इन दोनों दलों के नेतृत्व ने कुछ सीटें पाने के लिए कांग्रेस और क्षेत्रीय पूंजीवादी दलों को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने का तमगा देने की जी-जान से कोशिश की है। जबकि इस कांग्रेस ने धर्म से समझौता कर आजादी आन्दोलन का संचालन किया, सत्ता में आने पर धर्मान्धता-कट्टरता का इस्तेमाल किया, आरएसएस-भाजपा की तरह सांप्रदायिक दंगे करवाये, इनमें उल्लेखनीय हैं बिहार के भागलपुर में, उड़ीसा के राउरकेला में, असम में नेल्ली में अल्पसंख्यकों के खिलाफ और दिल्ली में सिख-विरोधी दंगे। क्या ये धर्मनिरपेक्षता के लक्षण हैं? सच्ची धर्मनिरपेक्षता यह है कि धर्म के साथ राजनीति, शिक्षा, संस्कृति का कोई संबंध नहीं होगा धर्म किसी व्यक्ति के विश्वास का विषय होगा। यह विचार यूरोप में पुनर्जागरण और लोकतांत्रिक क्रांति द्वारा लाया गया था। हमारे देश में नेताजी सुभाषचंद्र, भगत सिंह और रवींद्रनाथ, शरतचंद्र, नजरूल, प्रेम चंद, सुब्रह्मण्यम भारती, ज्योतिप्रसाद अग्रवाल ने इस देश में धर्मनिरपेक्षता के इस विचार का प्रचार किया। लेकिन समाजवादी क्रान्ति से भयभीत भारतीय पूंजीपति वर्ग और उसके प्रतिनिधि राष्ट्रीय कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व ने जिस तरह राजनीतिक रूप से सशस्त्र क्रांति का विरोध किया, उसी तरह सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में धार्मिक विचारों से समझौता किया, ताकि देश में वैज्ञानिक तर्कशील सोच विकसित न हो। परिणामस्वरूप, अल्पसंख्यक और तथाकथित निचली जातियों के अधिकांश लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को ऊंच जाति के हिंदू नेतृत्व के रूप में मान कर स्वतंत्रता आंदोलन से बाहर रहे। इसका फायदा उठाकर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, आरएसएस की सहमति से सांप्रदायिक दंगें करवा कर देश को दो टुकड़ों में बांट दिया।

स्वतंत्र भारत में सत्ता में रहते हुए, कांग्रेस ने न केवल इमरजेन्सी लगाई, बल्कि टाडा, मीसा, अफस्पा, यूएपीए जैसे काले कानून भी लागू किए। जन आंदोलन को दबाने के लिए सैकड़ों मजदूर, किसान, छात्र-नौजवान मरवाये। उस कांग्रेस को सीपीआई(एम) -सीपीआई लोकतांत्रिक कह रहे हैं। क्षेत्रीय पूंजीवादी दल तो विभिन्न प्रांतवाद, इलाकापरस्ती और जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। वे सभी धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए, वे भी कांग्रेस और भाजपा की तरह जन आंदोलन पर अत्याचार करते रहे हैं। इन पर भी सीपीआई(एम)-सीपीआई कुछ सीटें पाने के लालच में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक का लेबल लगा करके गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं। सीपीआई(एम) और सीपीआई के नेता कांग्रेस सहित इन सब पार्टियों के दर-दर पर गए, लेकिन सिर्फ डीएमके के सिवा किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया।

इस संदर्भ में, हम यह जोड़ना चाहते हैं कि जब भाजपा के विगत शासन के खिलाफ राज्य-राज्य में किसान-मजदूर-छात्रों का विक्षोभ अनायास स्वतःस्फूर्त फूट पड़ा था, तो हम चाहते थे कि वामपंथी इन आंदोलनों का एकजुट होकर नेतृत्व करें। अतः देश में वर्ग संघर्ष और जन आंदोलन को मजबूत किया जाए, तो जोरदार वाम-लोकतांत्रिक संयुक्त आंदोलन गठिन होगा। लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कांग्रेस के साथ समझौता करने में मशगूल रहे। नेतृत्वहीन हालत में, आंदोलनों में ठहराव आ गया। अतीत में भी, सीपीआई(एम)-सीपीआई ने इंदिरा कांग्रेस को 'धर्मनिरपेक्ष', 'लोकतांत्रिक' की संज्ञा देकर समर्थन दिया, सांप्रदायिकता के विरोध में आवाज उठा कर कांग्रेस के साथ समझौता किया। इसी तरह, वे 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में निर्मितं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इस मौके का फायदा उठा कर इस आंदोलन में प्रवेश कर आरएसएस-जनसंघ ने अपनी ताकत बढ़ाई। फिर से, 1977 के चुनावों में सीपीआई(एम) ने कांग्रेस की 'निरंकुशता' 'तानाशाही' के खिलाफ जनता पार्टी (जिसमें आरएसएस- जनसंघ शामिल थी) के साथ हाथ मिलाया। यही तर्क देकर, सीपीआई(एम)-भाजपा ने संयुक्त रूप से 1989 में वीपी सिंह सरकार का समर्थन किया। ज्योति बसु-वाजपेयी ने कोलकाता मैदान में एक साथ मिलकर सभा की थी। भाजपा के समर्थन से सीपीआई (एम) ने कलकत्ता निगम चलाया था। चुनावी स्वार्थ में इस तरह के निकृष्ट अवसरवाद पर उन्होंने बार-बार अमल किया है।

एसयूसीआई (सी) ने सदा क्रांतिकारी लाइन के आधार पर ही लड़ा चुनाव

जैसा कि आप जानते हैं, इस स्थिति में, हमारी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने सही मार्क्सवादी पार्टी होने के नाते कॉमरेड शिवदास घोष की निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर कई राज्यों में चुनाव लड़ा, यह जानते हुए कि हमें कोई सीट नहीं मिलेगी। पैसे के खेल और ध्रुवीकरण की हवा में, वोट भी कोई खास नहीं मिलेंगी। कॉमरेड शिवदास घोष ने हमें सिखाया है कि 'जब तक क्रांति नहीं होती, तब तक जनता चाहे या न चाहे, वह उसे अच्छा लगे या बुरा, जनता चुनाव में खींच ली जाती है। जनता आ जाती है। क्रांति का अर्थ है कि जब जनता यह समझ ले कि चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हर कोई इस चेतना के आधार पर संगठित हो जाता है और संगठित रूप से चुनावों का बहिष्कार कर देता है। नकारात्मक रूप से बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वे सकारात्मक रूप से विद्रोह या विद्रोह के स्तर पर चले गए हैं। जब वे कहते हैं कि नहीं, चुनाव नहीं, बल्कि सत्ता पर कब्जा करना है -केवल तभी चुनाव अकार्यकारी हो सकता है। अन्यथा, लोग बार-बार चुनावों में फंसते रहते हैं और जनता के साथ बने रहने के लिए, क्रांतिकारियों को भी चुनाव में जाना पड़ता है। अन्य कोई चारा न होने पर, जब सर्वहारा वर्ग क्रांतिकारी उद्देश्य को मद्देनजर रख कर जनता के साथ बने रहने के लिए चुनावी संघर्ष में उतरता है, तो वह लोगों

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कामरेड प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 2 का शेष)

की क्रांतिकारी राजनीतिक लाइन पर चुनावी संघर्ष में उतरता है। वह सीट जीतने की भी भरसक कोशिश करता है लेकिन उनके उद्देश्य का केंद्र बिन्दु कभी भी येन-केन प्रकारेण ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना नहीं होता है। उनका मुख्य केंद्र बिंदु जनता को एक महीने क्रांतिकारी लाइन के आधार पर चुनाव लड़ना सिखाना होता है, और ऐसा करते हुए, अगर अधिकतम सीट मिल जाएं, तो लेंगे, अगर नहीं मिलती हैं, चाहे एक भी सीट नहीं मिले, तो न मिले। ... लेकिन इसका मुख्य केंद्र बिंदु कभी नहीं होगा ... कि येन-केन प्रकारेण, जैसे-तैसे भी हो कुछ सीटें हड़पी जानी चाहिएं। ... दुश्मन को हराने के लिए आपको जो कुछ भी करना है, करो, अगर आप दलीलें देते हैं, क्रांतिकारी बिल्ला लगाए घूमते हैं, असल में जिस तरह पूंजीपति वर्ग चुनाव लड़ता है, आप भी क्रान्ति के नाम पर वही रणनीति, वही तौर-तरीका, कायदा लागू करने की कोशिश करते हैं। क्या यह क्रांतिकारी हो जाता है? इससे क्या क्रांति का काम आगे बढ़ता है? नहीं, यह क्रांतिकारी नहीं हो जाता है और इससे क्रांतिकारी काम आगे नहीं बढ़ता है।" इस शिक्षा से प्रेरित होकर, हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चुनावों में काम किया, और हमारी पार्टी के क्रांतिकारी वक्तव्य को देश भर में करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। कई लोगों ने यह सोच कर हमें वोट नहीं दिया कि हम जीतेंगे नहीं, यह बात सही है। लेकिन हमें नैतिक समर्थन दिया है, आम जनता ने हमारे उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे दाखिल कराने से लेकर चुनाव तक हर खर्च के लिए चंदा दिया है। घर-घर में, गली-कुंचों में, सड़कों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने चंदा किया है और लोगों ने गरीबों की पार्टी मान कर दिल खोल कर चंदा दिया है।

जैसा कि सर्वविदित है, कॉमरेड शिवदास घोष के उच्च आदर्शों से लैस, उनकी शिक्षाओं से शिक्षित हमारी पार्टी ने कभी भी खुद को उद्योगपतियों, बड़े-बड़े व्यापारियों को नहीं बेचा है, कभी भी पैसे के लिए उनके आगे हाथ नहीं फैलाये। पार्टी के रोजमर्रे के काम चलाने के लिए, किसी कार्यक्रम को करने के लिए, हम आम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और वे भी प्यार से खुल कर हमारी मदद करते हैं। वास्तव में, कई लोग प्यार वश मजाक में कहते हैं, "आप पागल हो, इसीलिए चुनावों में आप नहीं जीतते। दूसरी पार्टियां पैसा देती हैं, सुयोग-सुविधाएं देती हैं, तब वोट मांगती हैं। अखबार में, टीवी पर उनका कितना प्रचार होता है? जबकि आपका मीडिया में नामो-निशान तक नहीं होता है, आप चंदा चाहते हैं और वोट भी मांगते हो। आजकल ऐसी नीति-आदर्श मानकर भला कैसे चुनाव जीता जा सकता है?" हमारे कार्यकर्ता उन्हें कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाएं याद दिलाते हुए कहते हैं, "हमें वोट चाहे हमें मिलें या नहीं, आपका प्यार और समर्थन हमारा संबल है।" हम वोट के लिए मीडिया के पीछे-पीछे नहीं भागेंगे। इसी तरह एक क्रांतिकारी पार्टी के रूप में, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। इस बार हमें चुनावों में कोई सीट नहीं मिली है लेकिन हमें कई नए कार्यकर्ता और समर्थक, कई ईमानदार वामपंथी ख्यालात वाले लोग मिले हैं। इनमें मजदूर, किसान, नौजवान और महिलाएं हर तबके के लोग शामिल हैं। नई जगहों पर संपर्क मिले हैं, और लाखों लोगों का प्यार मिला है। उन्होंने बार-बार यह कहा है कि अन्य सभी लोग सड़-गल गए हैं, आप पर ही एकमात्र विश्वास है। आप तेजी से बड़ी पार्टी हो जाएं। चुनाव अभियान में मिली इस सफलता से, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोत्साहित, उत्तेजित और प्रेरित हैं। उनमें लेशमात्र भी निराशा-हताशा नहीं है। क्योंकि वे महान लेनिन-स्टालिन-माओ त्से तुंग-शिवदास घोष की शिक्षाओं से जानते हैं कि रूस, चीन, वियतनाम, कहीं भी चुनावों से, सीटों के बल पर कोई क्रांति नहीं हुई थी; क्रांति क्रांतिकारी आदर्श-विचार से शिक्षित, सुसंगठित, उन्नत नैतिक शक्ति से लैस क्रांतिकारी जनशक्ति से होती है।

भाजपा की ताकत में बढ़ोतरी का कारण

इस क्रांति की तैयारी के तौर पर, पूँजीवाद के खिलाफ व्यापक मजदूर वर्ग का वर्ग संघर्ष और जनांदोलन चाहिए। संसदीय लोकतंत्र संसदीय फासीवादी निरंकुशता बन गया है। भले ही संसद में तमाम ठाठ-बाट हैं। कॉमरेड शिवदास घोष ने 1948 में ही यह चेतावनी दे दी कि भले ही फासीवादी जर्मनी-इटली द्वितीय विश्व युद्ध में हार गये थे, लेकिन तरह-तरह के रूपों में फासीवाद दुनिया के उन्नत और अनुन्नत, विकसित-विकासशील सभी देशों की विशेषता बन गया है। उन्होंने यह कहा था कि फासीवाद एक असली इन्सान बनने की प्रक्रिया को खत्म कर देता है। अंधता, कट्टरता, अतार्किकता, अंधराष्ट्रवाद, रूढ़िवाद-परंपरावाद, इन सबकों फासीवाद उभार रहा है। कांग्रेस ने ही इस देश में फासीवाद की नींव रखी। आज भाजपा सत्तारूढ़ होकर फासीवाद को और भी मजबूत कर रही है। आपको यह समझना होगा कि भाजपा 3ऐसे कैसे ताकत बढ़ा पायी। पूंजीपति वर्ग की चौतरफा मदद तो इसके पीछे है ही, जैसे कि पहले कांग्रेस को भी यह मदद मिली है। इसके अलावा, भाजपा की ताकत में इस वृद्धि के तीन मुख्य कारण और भी हैं। सबसे पहला, क्रान्ति के डर से राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के युग में, सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति का रास्ता अपनाने की बजाय धार्मिक सोच, परंपरावाद, रंगभेद, प्रांतवाद, क्षेत्रीयता आदि से समझौता किया। परिणामस्वरूप, समाज में वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक विचारधारा और सच्ची धर्मनिरपेक्षता विकसित नहीं हो सकी। एकीकृत सीपीआई ने भी इसके खिलाफ कोई प्रभावी आंदोलन नहीं किया। नतीजतन, देश की धरती पर धार्मिक भावनाएं, विशेष रूप से हिंदू धार्मिक भावनाएं, धर्मगत-जातिगत नस्लीय बैरभाव बचा रह गया। स्वतंत्रता आंदोलन चलने के दौरान एक प्रकार की राजनीतिक एकता थी जो उभर कर उतनी नहीं आ सकी। लेकिन बाद में, इस हिंदू भावना और परंपरावाद का इस्तेमाल करते हुए, आरएसएस और पूर्ववर्ती जनसंघ और वर्तमान में भाजपा ने सिर उठाया। दूसरा, शक्तिशाली वामपंथी और लोकतांत्रिक आंदोलनों की अनुपस्थिति ने उनको एक मौका दे दिया। प्रमुख वामपंथी पार्टियों सीपीआई, सीपीआई (एम) के नेतृत्व ने केवल इतना ही नहीं कि इन मध्ययुगीन प्राचीन, सामंती सोच और विचारों के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक प्रभाव से मुक्त मानवतावाद पर आधारित सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि यहां तक कि अविभाजित सीपीआई ने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सुर में सुर मिलाते हुए हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग राष्ट्र हैं, यह अजीबोगरीब सिद्धांत रच कर देश के विभाजन का भी समर्थन किया था। इन सभी ने आरएसएस को मजबूत करने का काम किया। इसे आप याद रखें। तीसरा, आपको एक अन्य महत्वपूर्ण कारण को भी ध्यान में रखना होगा, वह यह है कि विश्व साम्राज्यवाद-पूंजीवाद के खिलाफ जब तक महान स्टालिन और माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में मजबूत विश्व समाजवादी व्यवस्था उभर कर आ गई थी, औपनिवेशिक अर्द्ध-उपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद-विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन, देश में श्रमिक आंदोलन, जनवादी आन्दोलन और जन आंदोलन जोर-शोर से चल रहे थे। युद्ध-विरोधी शांति आंदोलन भी उठ खड़े हो गये थे। इस स्थिति में, साम्राज्यवाद-पूंजीवाद का प्रतिक्रियात्मक चरित्र रहने के बावजूद, लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक तर्क, प्रगतिशील मानसिकता का दुनिया भर में बोलबाला था। लेकिन साम्राज्यवादी साजिशों और आंतरिक पूंजीवादी प्रतिक्रान्ति के परिणामस्वरूप समाजवाद के ढह जाने के साथ ही पूरी दुनिया में आज धार्मिक कट्टरता, अंधराष्ट्रवाद, साम्प्रदायिकता, नस्लवाद, जातिवाद, मध्ययुगीन प्रतिक्रियावादी सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोणरहित अंधी मानसिकता आदि प्रतिक्रियावाद का सैलाब सा आ गया है। यह स्थिति भी आरएसएस-भाजपा के उभरने में मदद कर रही है। इस संदर्भ में, मैं आपको विश्व-प्रसिद्ध मनीषी रोमां रोलां की एक चेतावनी पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने 1932 में कहा था, "आज पृथ्वी पर सोवियत लोकतंत्र के खिलाफ एक भयानक साम्राज्यवादी शक्ति लामबंद हो गई है। ... यदि इसे नेस्तनाबूद नहीं किया गया, तो न केवल सर्वहारा वर्ग जर-खरीद गुलाम हो जाएगा, बल्कि सामाजिक या व्यक्तिगत हर तरह की स्वतंत्रता ही समाप्त कर दी जाएगी। दुनिया कई युग पीछे धकेल दी जाएगी ... कुछ शताब्दियों के लिए, वहाँ अंधेरा गहरा जाएगा।" [1] वास्तव में ऐसा ही हुआ है, आप आज की दुनिया को देखकर यह बखूबी समझ सकते हैं।

वैज्ञानिक, तर्कशील मानसिकता को खत्म करना चाहती है भाजपा

आज, जो लोग प्रचार से गुमराह हैं या आर्थिक और अन्य सुयोग-सुविधाएं पाने के लोभ-लालच में आरएसएस-भाजपा का झंडा लेकर चल रहे हैं, क्या वे जानते हैं कि आरएसएस-भाजपा इस देश में नवजागरण की मानसिकता के आदर्शों और भूमिका को पूरी तरह से नकार रही है? राममोहन राय ने इस देश के पुनर्जागरण के उषाकाल में कहा था, "अब हम पाते हैं कि (अंग्रेजी) सरकार हिन्दू पंडितों के तहत संस्कृत स्कूल स्थापित करने जा रही है ऐसा ज्ञान प्रदान करने के लिए जो पहले ही भारत में है। इससे छात्र वही ज्ञान प्राप्त करेंगे जो 2 हजार साल पहले ज्ञात था। नतीजतन झूठा अहंकार पैदा होगा। जो लोग अटकलबाज हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, उनके द्वारा पनपायी गई अन्त:सारशून्य दुर्बोध सोच को ही बढ़ावा मिलेगा। ... न ही वेदांत की शिक्षा से युवक समाज के बेहतर नागरिक बनने के काबिल होंगे जो यह विश्वास करना सिखाता है कि किसी दृश्यमान चीज का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ...संस्कृत शिक्षा पद्धति देश को अंधेरे में रखने की सुपरिकल्पित मंशा होगी यदि ब्रिटिश विधायिका की यही नीति रही तो। लेकिन देशी आबादी का सुधार करना क्योंकि सरकार का लक्ष्य है, अत: वह अन्य उपयोगी विज्ञानों के साथ-साथ अंकगणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र और शरीर रचना विज्ञान को शामिल करते हुए, शिक्षण की उदार और प्रबुद्धकारी व्यवस्था को और भी बढ़ावा देगी।" [2] उनके पदचिन्हों पर चलते हुए, पुनर्जागरण के सूर्ख सूरज के दौर में विद्यासागर ने कुछ कदम आगे बढ़ते हुए, यह कहा था, "यह आज विवाद का विषय नहीं है कि सांख्य और वेदांत भ्रान्तिपूर्ण दर्शन हैं।...इसलिए हमें यूरोप के ऐसे दर्शनों को पढ़ाने की जरूरत है, जिन्हें पढ़ने से हमारे देश के युवा समझेंगे कि वेदांत और सांख्य भ्रांतिपूर्ण दर्शन हैं।...भारतीय विद्वानों की रूढ़िवादिता अरब के खलीफाओं की रूढ़िवादिता से कुछ कम नहीं है। उनका विश्वास है कि जिन ऋषियों के मस्तिष्क से इन शास्त्रों का सृजन हुआ है, वे सर्वज्ञ हैं। अत: उनके द्वारा रचे गये शास्त्र गलतियों से परे हैं।...जहां भी आधुनिक यूरोपीय ज्ञान का प्रकाश पहुंचा है, वहां स्वदेशी शास्त्रीय शिक्षा का प्रभाव उतना ही कम होता जा रहा है। इस शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाया जाना चाहिए। ... भूगोल, इतिहास, जीवन-चरित्र, अंकगणित, रेखागणित, प्राकृतिक दर्शन, नैतिक दर्शन, शरीर क्रिया विज्ञान, राजनैतिक अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़ाने चाहिएं। ...हमें ऐसे शिक्षकों की जरूरत है, जिन्हें बंगाली और अंग्रेजी भाषा की जानकारी हो और साथ ही वे धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हों।" [3] बहुत से लोग यह नहीं जानते, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भगवान को नहीं मानते थे। उन्होंने दीक्षा नहीं ली। वे किसी मंदिर में नहीं गए। उनकी पाठ्यपुस्तक में ईश्वर या अलौकिक सिद्धांत की चर्चा नहीं है। जिसके किारण अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी बिशप मर्डाक ने उन्हें 'रैंक भौतिकवादी'('चरम भौतिकवादी') कहा था। लेकिन रामकृष्ण इस विद्यासागर को आदर-सम्मान देने उनके घर गए थे। विवेकानंद ने कहा कि रामकृष्ण और विद्यासागर उनके आदर्श थे। समकालीन महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले भी पश्चिम की वैज्ञानिक शिक्षा के पक्ष में थे। देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार जहां संस्कृत और धार्मिक भाववादी दर्शन पढ़ाने पर जोर दे रही थी, वहीं राममोहन, विद्यासागर, फुले द्वारा उसका विरोध किया गया। विद्यासागर के अनुगामी क्रांतिकारी मानवतावादी साहित्यकार शरतचंद्र ने भी ऊँची आवाज में कहा, "... कोई भी धर्म-ग्रंथ झूठ से परे नहीं हो सकता। वेद भी धर्म-ग्रंथ है। इसलिए इसमें भी झूठ की कमी नहीं है।...सभी धर्म झूठे हैं--आदिम काल के अंधविश्वास हैं। मानव सभ्यता का इतना बड़ा दुश्मन और कोई नहीं हो सकता।" [4] वैज्ञानिक तर्कसंगत शिक्षा का महत्व और पुरातन रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त मानसिकता तैयार हो - पुनर्जागरण का यह आह्वान रवींद्रनाथ, प्रेमचंद, सुब्रह्मण्यम भारती, ज्योति प्रसाद अग्रवाल और नजरुल की साहित्यिक रचनाओं में था। लेकिन आरएसएस-भाजपा इस सब का विरोध करती है। वे अंग्रेजी के महत्व को कम कर रहे हैं और संस्कृत शिक्षण पर जोर देकर हिंदू धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में देश को ले जा रहे हैं। यूरोपीय और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की सभी खोजों को खारिज कर वे इन सभी असत्यों पर विश्वास करने की मांग कर रहे हैं कि 'सब कुछ वेदों में है', प्राचीन ऋषि-मुनि सारे आविष्कार कर गए हैं। खुद प्रधानमंत्री द्वारा यह कहना कि प्लास्टिक सर्जरी करके गणेश का सिर जोड़ा गया, जैसी बातों से लेकर, उनके चापलूस कुछ विद्वान हास्यास्पद बेसिर-पैर की कहानियां फैला रहे हैं। हालांकि, उन्होंने अभी तक यह दावा नहीं किया गया है कि हाल ही में छोड़ा गया चंद्रयान किसी वैदिक शास्त्र के मंत्र के अनुसार बनाया गया है। जबकि इस क्षेत्र में एक समय था जब इस भूखण्ड पर धर्मशास्त्र के बल पर नहीं, बल्कि इसका विरोध करके ही सही मायने में विज्ञान साधना हुई थी। खासकर बौद्ध धर्म के युग में, विज्ञान की बहुत प्रगति हुई थी, जो बाद में वेदांत के प्रभाव से अवरुद्ध हो गई थी। आधुनिक भारतीय विज्ञान के अग्रदूतों में से एक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने यह शिकायत स्वयं की थी। यूरोप में धार्मिक न्यायविचार करने वालों ने विज्ञान साधना में लगे हुए गैलीलियो और ब्रुनो जैसे कई लोगों को बेरहमी से सताया गया है और यहां तक कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके विरोध में, विवेकानंद ने कहा, "हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में आधुनिक खगोलशास्त्री और भातिक वैज्ञानिक क्या सोचते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि इसने यूरोप के प्राचीन धर्मशास्त्रियों की कितने दुखद ढंग से क्षति पहुंचाई है। जिस तरह एक एक नई वैज्ञानिक खोज की जा रही है, उन खोजों के द्वारा मानो उनके गढ़ों पर बम गिराए गए हैं, और हम जानते है कि कैसे उन धर्मशास्त्रियों ने सभी युगों में इन सभी वैज्ञानिक खोजों को दबा देने की कोशिश की है।" [5] हिंदू धर्म के प्रमुख पैरोकारों में से एक विवेकानंद के इस कथनानुसार आरएसएस-भाजपा की भूमिका पर विचार किया जाए, तो वह क्या नजर आती है? अंतर यह है कि विवेकानंद के विचार के अनुसार, आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड के बारे में नई-नई खोज कर रहा है, जिससे आतंकित होकर प्राचीन धर्मशास्त्रियों ने विज्ञान की प्रगति को बाधित करने की कोशिश की थी। जबकि वर्तमान हिंदुत्ववादी यह दावा कर

(शेष पृष्ठ 4 पर)

कामरेड प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 3 का शेष)

रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान के द्वारा कोई नया आविष्कार नहीं किया हुआ है, सभी खोज प्राचीन हिंदू ऋषि-मुनि कर गए हैं। क्या वे ऐसा नासमझी में कर रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। उनका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के महत्व को नकार कर वैज्ञानिक तर्कसंगत दिमाग विकसित करने की प्रक्रिया को समाप्त करना है और प्राचीन धार्मिक परंपरावाद की ओर देश की सोच को प्रतिगामी करना है, ताकि एक फासीवादी अंध विश्वास तैयार किया जा सके। एक अन्य मंशा यह है कि हिन्दू धार्मिक कट्टरता को उकसाकर और सांप्रदायिक नफरत की आग भड़काकर मारकाट मचवा कर लोगों की एकता को तोड़ना है, जैसा कि अंग्रेजों ने एक समय किया था, और एक हिंदू वोट बैंक बनाना। दूसरी ओर, घोर दुर्दशाग्रस्त लोग ताकि पूंजीवाद और सरकार के खिलाफ विक्षुब्ध न हों, इसलिए उनकी दु:ख-तकलीफें, बेरोजगारी, भुखमरी, बेइलाज मौत, ये सब उनके पूर्वजन्मों के पापों के फल हैं, सब नियति के विधान हैं, भगवान की मर्जी है, नसीब का खेल है, भाग्य में लिखे लेख हैं, इस जन्म में हंसते-हंसते दु:ख झेलोगे, तो अगले जन्म में भगवान सुख देंगे- इन धार्मिक प्रवचनों में आम लोग भ्रमित और अंधे बना कर रखे हुए हैं। किसी ईमानदारीपूर्ण धार्मिक विश्वास से नहीं, अत्यंत दुरभिसंधिपूर्ण षड्यंत्र रच कर ही आरएसएस-भाजपा यह सब कर रही है। लोगों को सोच कर देखना होगा कि क्या वे भारतीय नवजागरण के मनीषियों के महान आदर्शों और संघर्षों को नजरअंदाज करके और आधुनिक विज्ञान को अस्वीकार कर आरएसएस-भाजपा की इस साजिश का समर्थन करेंगे? क्या इससे देश और भी रसातल में नहीं चला जाएगा? क्या इससे मानवता का परम शत्रु फासीवाद मजबूत नहीं हो जाएगा?

हिंदुत्ववादियों ने भारत के आजादी आंदोलन का किया था विरोध

एक अन्य विषय को भी हम देश के लोगों को फिर से विचार करने के लिए उठाना चाहते हैं। क्या वे जानते हैं कि सैकड़ों शहीदों के खून से सींचे हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को 'प्रतिक्रियावादी' करार देकर आरएसएस ने इसका पूर्ण विरोध किया था। इसी वजह से, आरएसएस किसी भी चरण में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। क्योंकि आरएसएस के गुरु गोलवलकर का कहना है, "भौगोलिक राष्ट्रवाद और आम खतरे के सिद्धांत के आधार पर हमारा जो राष्ट्रीय सिद्धांत निर्मित हुआ है, उसने हमें हमारे हिन्दू राष्ट्रवाद के सिद्धांत के सकारात्मक और प्रेरणादायक तत्व से वंचित कर दिया है और हमारे स्वाधीनता आंदोलन को दरअसल अंग्रेज-विरोधी आन्दोलनों में तब्दील कर दिया है। अंग्रेज-विरोध को देशप्रेम और राष्ट्रवाद का पर्यायवाची बना दिया गया है। इस प्रतिक्रियावादी धारणा ने सम्पूर्ण स्वाधीनता आन्दोलन, उसके नेतृत्व और आम लोगों पर विनाशकारी असर डाला है। ...वे एकमात्र राष्ट्रवादी देशभक्त हैं जो अपने लक्ष्य में हिंदू राष्ट्र का सम्मान करते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। देशभक्ति का ढोंग करने वाले बाकी लोग हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं और देश के दुश्मन हैं।"[6] जरा सोच कर देखिए यह वक्तव्य कितना भयंकर है चूंकि हिन्दू राष्ट्रीय चिन्तन द्वारा आजादी आन्दोलन संचालित नहीं हुआ था, पूरा आजादी आन्दोलन और इसके नेता देशबंधु, लाला लाजपत राय, तिलक से लेकर नेताजी, खुदीराम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, प्रीतिलता, यहां तक कि गांधीजी, नेहरू तक भी वास्तव में, सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से तो 'प्रतिक्रियावादी', 'गद्दार' और 'दुश्मन' करार दिये जाएंगे। क्या देश के लोग भाजपा के जनक, आरएसएस के इस बयान को स्वीकार करेंगे? क्या वे गौरवशाली स्वतंत्रता आंदोलन, मुक्ति आंदोलन के आदर के योग्य नेताओं और महान शहीदों का अपमान करेंगे? हालांकि, सरकारी सत्ता हासिल करने और मीडिया के प्रचार के बल पर, आरएसएस के नेता आज खुद को जाहिराना तौर पर देशभक्त, स्वतंत्रता के रक्षक होने का दिखावा करते हैं। आज, यह बात कम ही लोग जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोस्ती करके गठबंधन करके सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और अविभाजित बंगाल में मंत्रिमंडल का गठन किया था। फजलुल हक अविभाजित बंगाल के मुख्यमंत्री थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे। अगर कोई भी इस बात को गलत साबित कर दे, आगे आए। लेकिन हम तथ्यों के साथ यह साबित कर सकते हैं।

गोलवलकर ने यह भी कहा, "हिन्दुस्थान के सभी गैर हिन्दुओं को या तो हिन्दू भाषा और संस्कृति अपनानी होगी। उन्हें हिन्दू धर्म का आदर करना होगा और उसे पवित्र मानना सीखना होगा। वे हिन्दू राष्ट्र की गौरव गाथा के अतिरिक्त अन्य किसी विचार को प्रश्रय नहीं देंगे और हिन्दू नस्ल में मिल जाने के लिए अपने पृथक अस्तित्व को उन्हें खो देना होगा या उन्हें बगैर किसी माँग के और बगैर किसी विशेषाधिकार के, बगैर किसी तरह की रियायत के, यहाँ तक कि बगैर किसी नागरिक अधिकार के इस देश में पूरी तरह से हिन्दू राष्ट्र के अधीन रहना होगा।"[7]- कितनी भयंकर साम्प्रदायिकता है। आज यह बात जबान से न कहने पर भी, आरएसएस-भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की विभिन्न टिप्पणियों और कार्यों से स्पष्ट है यही मनोभाव प्रकट होता है। इस मनोभावना के विरोध में, नेताजी सुभाष चंद्र ने 1940 में एक सभा में कहा था, "... धर्म का फायदा उठा कर और उसे मलिन कर हिन्दू महासभा ने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया है। ... उसकी निंदा करना सभी हिंदुओं का ही कर्तव्य है।"[8] एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा था, "... हिन्दू भारत में बहुसंख्यक होने की वजह से हिन्दू राज की गूंज सुनाई दे रही है। यह सब बेकार विचार हैं।"[9] उन्होंने आगे कहा था, "तुच्छ निजी स्वार्थों में एक वर्ग के इच्छुक लोग दो समुदायों (हिंदू और मुस्लिम) के बीच टकराव और विवाद पैदा कर रहे हैं - इस वर्ग के लोगों को भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में दुश्मन माना जाना चाहिए।"[10] नेताजी ने धर्मवर्जित राजनीति अर्थात् धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए कहा था, "धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर आदमी जिस धर्म को चाहे, उसका अनुसरण करने की उसे पूरी आजादी होनी चाहिए। लेकिन धार्मिक या अतिप्राकृत धारणाओं द्वारा राजनीति संचालित नहीं होनी चाहिए। राजनीति का संचालन मात्र आर्थिक, राजनैतिक व वैज्ञानिक तर्क-विचार द्वारा होना चाहिए।"[11] रवीन्द्रनाथ ने कहा था, "जो देश केवल धर्म के मेल से ही एक दूसरे को मिलाता है, अन्य किसी बंधन में उसे बांध नहीं सकता, वह देश सौभाग्यशाली नहीं है। वह धर्म स्वयं धर्म के जरिए जो विभेद पैदा करता है वह सबसे ज्यादा विनाशकारी विभेद है।"[12]) शरतचंद्र ने कहा था, "केवल महामानवता का आदर्श ग्रहण करो, उसे भारत का आदर्श, एशिया का आदर्श, हिंदू आदर्श -इस पहलू से विचार बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यह तंगदिल का संकीर्ण घटिया आदर्श, किसी भी तरह से एक सार्वभौमिक मुक्त आदर्श नहीं है।"[13] फिर उन्होंने दु:ख होकर यह भी कहा था, "जिन्हें सन्यासी होना चाहिए था, वे तो हो गए हैं पॉलिटिशियन, इसीलिए तो भारत की पॉलिटिक्स की इतनी दुर्गति है।"[14] 25 वर्षीय भगत सिंह जिसे एक समय देशवासियों ने 'शहीद-ए-आजम' के दर्जे सें विभूषित किया, उस भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पर अपना बलिदान देने से पहले अपना अमूल्य निबंध 'मैं नास्तिक क्यों' लिखा था ताकि देशवासी, विशेष कर छात्र-नौजवान इस विचार से प्रेरित हों। क्या आज देश के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग सुभाषचंद्र, रवींद्रनाथ, शरतचंद्र, भगत सिंह सहित उस युग के अन्य महापुरुषों की इन सब महान शिक्षाओं का विसर्जन कर देंगे और आरएसएस-भाजपा के झण्डे तले चले जाएंगे?

मैं उन लोगों को विवेकानंद की कुछ उक्तियां सुनाना चाहूंगा जो ईमानदारी से हिंदू धर्म को मानते हैं। उन्होंने कहा था, "किसी भी धर्म ने कभी किसी आदमी पर अत्याचार नहीं किया है, किसी भी धर्म ने डाइन होने का लांछन लगाकर कभी किसी महिला को जला कर नहीं मारा है, फिर लोगों को ऐसा करने के लिए किसने प्रेरित किया? यह राजनीति है जिसने लोगों को इन गलत कामों के लिए उकसाया है, न कि धर्म ने।"[15] शिकागो में दिये गए अपने भाषण में उन्होंने यह भी कहा था, "साम्प्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी वीभत्स वंशधर धर्मान्धता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी हैं। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारम्बार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं।"[16] विवेकानंद के इस कथन की रोशनी में, एक बार आरएसएस-भाजपा के बयानों और गतिविधियों पर जरा सोचविचार करके देखें। क्या वे वास्तव में हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं? विवेकानंद ने यह भी कहा था, "हम मानव जाति को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ न तो वेद हो, न ही बाइबल और न ही कुरान हो, वेद, बाइबिल और कुरान को मिलाकर ऐसा समन्वय करना पड़ेगा। . .. हम केवल सभी धर्मों को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को अच्छा मानते हैं ... यदि मेरा कोई बेटा होता, तो ध्यान लगाने और साथ में एक पंक्ति की प्रार्थना व मंत्र जपने के अलावा उसे मैं और किसी तरह की धर्म की बात सीखने नहीं देता। तत्पश्चात, बड़ा होकर और विभिन्न रायों व परामर्शों को सुनते हुए वह उन सबसे अवगत हो जाता जो उसे सत्य लगते। फिर वह मसीह, बुद्ध या मोहम्मद की पूजा करने के लिए बढ़ सकता है। ..इसलिए यह नितांत स्वाभाविक है कि एक ही साथ पूरी तरह से स्वतंत्र और निर्विघ्न रूप से मेरा बेटा बौद्ध, मेरी पत्नी ईसाई और मैं स्वयं मुसलमान हो सकता हूँ।"[17] क्या आरएसएस-भाजपा के नेता इस विवेकानंद को हिंदू मानेंगे या उन्हें विधर्मी कहेंगे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण ने तो मस्जिद तक में नमाज तक अदा की थी। उन्होंने चर्च में भी प्रार्थना की थी और बहुत ही सरल शब्दों में कहा था, "जिसे आप कृष्ण कहते हैं, उसे ही शिव, उसे ही आदित्य कहा जाता है, उसी को ईसा मसीह कहा जाता है, उन्हीं को अल्लाह कहा जाता है। ... वस्तु एक ही है, नाम अलग हैं। ... एक तालाब में कई घाट हैं। हिंदू एक घाट से पानी लेकर कलसी भर रहे हैं, कहते हैं जल। मुसलमान एक दूसरे घाट से पानी लेकर चमड़े के डोल में भर रहे हैं, उसे कह रहे हैं पानी। ईसाई तीसरे एक घाट पर पानी लेकर, उसे वाटर कहते हैं।"[18] अर्थात् ईश्वर, गॉड, अल्लाह एक ही है। आरएसएस-भाजपा के नेता इस रामकृष्ण को क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे कि उन्होंने हिंदू धर्म-विरोधी बात की और धर्म-विरोधी आचरण किया?

वे रामचंद्र के जन्मस्थान का दावा करते हैं, जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म की प्राचीन मूर्तियों को तोड़ दिया था, उसी तरह अयोध्या में ऐतिहासिक स्मारक बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इस संदर्भ में, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि चैतन्य, रामकृष्ण, विवेकानंद, जिन्हें हिंदू धर्म के पैरोकारों के रूप में जाना जाता है, विख्यात हैं और जो हिंदुओं के पूजनीय हैं, उन्होंने कभी इस मांग को क्यों नहीं उठाया? क्या वे कायर थे? ऐसा कहा जाता है कि बाल्मीकि ने रामायण की रचना राम के जन्म से बहुत पहले ही कर दी थी, तुलसीदास ने रामायण तब लिखी थी जब बाबरी मस्जिद बरकरार थी। इन दोनों रामायणों में कहीं भी तो यह उल्लेख नहीं है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण राम के जन्म स्थान पर हुआ था। अब इस संबंध में विवेकानंद का कथन सुनिए। वह कहते हैं, "रामायण को ही ले लीजिए ...उसको एक प्रामाणिक रचना की दृष्टि से देखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राम के समान कोई व्यक्ति कभी रहा होगा। ...पुराणों के दार्शनिक सत्य के मूल्यांकन के उद्देश्य से हमें इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें जिन व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, वे वास्तव में हाड़-मांस के मनुष्य थे अथवा कल्पित मात्र।"[19] विवेकानंद ने राम के वास्तविक अस्तित्व की इतनी साफ अस्वीकृति दी है कि खोजने से ही मना कर दिया, सिर्फ रामायण से ही शिक्षा लेने को कहा। आज भी, जो लोग ईमानदारी से हिंदू धर्म को मानते हैं, वे सोच सकते हैं कि रामकृष्ण-विवेकानंद की शिक्षाओं पर चलते करते हुए आरएसएस-भाजपा वास्तव में हिंदू धर्म का अनुसरण कर रही हैं? या वे तुच्छ राजनीतिक निहित स्वार्थों के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। यही बात इस देश और विदेश के मुस्लिम कट्टरपंथियों पर भी लागू होती है। वे हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, सत्ता पाने की लालसा और हीन राजनीतिक हितों में इस्लाम धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

यह चिंता की बात है कि जिस अविभाजित बंगाल और उसके बाद पश्चिम बंगाल में आरएसएस, हिंदू महासभा और डॉ. श्यामाप्रसाद जैसी हस्तियां जगह नहीं बना सकीं, उसी पश्चिम बंगाल में आज भाजपा तृणमूल कांग्रेस-विरोधी मानसिकता का फायदा उठाकर अपना सिर उठा रही है। आपको सोचना होगा, उस समय वे ऐसा क्यों नहीं कर सकी थी, और आज वे कैसे कर पा रही हैं? इसे समझने के लिए, हमें अतीत के भूल-बिसरे एक अध्याय को याद करना होगा जिसे परिचित अस्सी साल की उम्र पार कुछ मुट्ठीभर बुजुर्ग अभी भी जीवित हैं, बाकी मर चुके हैं और बाद वाली पीढ़ी उन बातों से अनजान है। बंगालियों की किसी विशेषता के कारण नहीं, चूंकि ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में कलकत्ता राजधानी थी और यहीं पर पहले पहल अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता की रोशनी पहुंची थी। इसके चलते यहां पहले आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, साहित्य-संस्कृति का विकास हुआ, भारतीय पुनर्जागरण और क्रांतिकारता की शुरुआत हुई। इसे देखकर मोहित हो गए गोखले ने जो कहा था, 'व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमॉरो'। यहीं पर सशस्त्र क्रांतिकारिता और नेताजी को केंद्र करके वामपंथ का गढ़ बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिन के नेतृत्व में फासीवाद की हार, समाजवाद की विशाल प्रगति, चीन में कम्युनिस्ट क्रांति की सफलता ने इस देश में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मार्क्सवाद-साम्यवाद के प्रति शिक्षित लोगों के तबके को आकर्षित किया था। परिणामस्वरूप, यहां के लोगों, विशेष रूप से शिक्षित समाज-छात्र-युवा समुदाय ने घोर प्रतिक्रियावादी आरएसएस और बाद में जनसंघ की धार्मिक सांप्रदायिक मानसिकता को नहीं अपनाया। आपको याद होगा, लोगों की इस वामपंथी मानसिकता का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में सीपीआई और सीपीआई (एम) मजबूत वामपंथी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। सन् 1952 में हुए पहले चुनाव में सीपीआई ने कोलकाता में लोकसभा और विधानसभा की अधिकांश सीटें जीतीं। सन् 1952 में ट्राम भाड़ा वृद्धि-विरोधी आंदोलन, 1954 में शिक्षक आंदोलन, 1953 में बंगाल-बिहार विलय-विरोधी आंदोलन, 1959 में खाद्य आंदोलन और 1966 में फिर खाद्य आंदोलन जुझारू वामपंथी धारा में किये गये। सीपीआई(एम) और सीपीआई सही

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कामरेड प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 4 का शेष)

मार्क्सवादी पार्टियां नहीं होते हुए भी इस दौरान जुझारू वामपंथ पर अमल करती थीं। हालाँकि हमारी पार्टी आज की तुलना में उन दिनों छोटी थी, लेकिन फिर भी इन संयुक्त आंदोलनों में हमारी पार्टी की क्रांतिकारी लाइन और उनकी सुधारवादी चुनावी-लाइन के बीच द्वंद्व-संघर्ष था। इस दौरान इन आंदोलनों में कांग्रेस सरकार के दमन-उत्पीड़न के चलते कई छात्र शहीद हुए, घायल हुए और सैकड़ों को जेलों में ठूंस दिया गया। उसी समय, घबराए हुए भारतीय पूंजीवाद और कांग्रेस नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोलकाता को 'बुरे सपने का शहर' कहा था। उसी तरह जिस तरह पहले ब्रिटिश साम्राज्यवाद अविभाजित बंगाल को, कोलकाता को डरी हुई नजरों से देखते थे। इन जुझारू वामपंथी आंदोलनों को औजार बनाकर ही पहले एकीकृत सीपीआई और बाद में सीपीआई(एम) ने अपना प्रभाव बढ़ाया। लेकिन उन्होंने नेताओं, कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच मार्क्सवाद की वैचारिक चर्चा तो दूर की बात रही, वामपंथी राजनीति और संस्कृति पर भी अमल नहीं किया और धर्मान्धता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, प्रांतवाद के खिलाफ कोई सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन नहीं खड़ा किया। परिणामस्वरूप, मार्क्सवाद और वामपंथ के प्रति अंध आवेग और नारेबाजी के आधार पर वामपंथी मानसिकता का निर्माण हुआ और पार्टी के अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं और प्रभावित लोगों के बीच विभिन्न धार्मिक और अन्य अंधविश्वासों व कुसंस्कारों का प्रभाव था और हिंदू-मुस्लिम भावना भी सुप्त रूप में व्याप्त थी। इस सब के बावजूद, आम लोग वामपंथ की ओर आकर्षित हुए थे। शक्तिशाली जन आंदोलनों के प्रभाव और कांग्रेस-विरोधी भावना के कारण, कांग्रेस को 1967 में विधानसभा चुनावों में हार मिली और पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) सहित सीपीआई(एम), सीपीआई, अन्य वामपंथी दलों और बांग्ला कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों को लेकर संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी। आज यह बात कइयों को पता नहीं है कि उस समय संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन से पहले कार्यक्रम तैयार करने में हमारी पार्टी के साथ सीपीआई(एम) सहित अन्य कई दलों के गंभीर मतभेद दिखाई दिए थे। लेनिन के समय में, मार्क्सवादियों के पास सरकार बनाने का मौका नहीं आया था, इसलिए उन्होंने बुर्जुआ राज्य में संसद में विपक्षी पार्टी की भूमिका मार्क्सवादी निभायेंगे, इसके बारे में उन्हें दिशानिर्देश दिया था। नतीजतन, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार, कॉमरेड शिवदास घोष ने सरकार चलाने के लिए एक ऐतिहासिक दिशानिर्देश प्रस्तुत किया था। हमारी पार्टी का प्रस्ताव था कि संयुक्त मोर्चा सरकार मेहनतकश लोगों- मजदूरों, गरीब किसानों के वर्ग संघर्ष और जन आन्दोलनों को प्रोत्साहित करेगी, और न्यायसंगत जन आन्दोलनों पर पुलिस पहले वाली सरकारों की तरह हमला नहीं करेगी। सीपीएम सहित अन्य दल इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तब हमारी पार्टी ने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे और बाहर से समर्थन करेंगे। उस समय, सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों की जो जुझारू मानसिकता थी, उससे हमारे सरकार में शामिल न रहने से वे पार्टियां सवालों का निशाना बन जाएंगी, इसी वजह से सीपीआई (एम) के नेताओं और अन्य लोगों ने आखिरकार, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यह मानते हुए कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) छोटी पार्टी है, परिणामस्वरूप वह कुछ विशेष नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारी पार्टी की तत्कालीन केन्द्रीय कमेटी के प्रमुख नेता कामरेड सुबोध बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से संयुक्त मोर्चा सरकार के श्रम मंत्री के रूप में घोषित किया कि संयुक्त मोर्चा सरकार की नीति है न्यायसंगत जन आंदोलन में पुलिस दखलअंदाजी नहीं करेगी। इसने पूरे पश्चिम बंगाल में मजदूरों, किसानों और अन्य लोगों के संघर्षों और जन आंदोलनों की लहर पैदा कर दी। गली-गली से नारा लगने लगा संयुक्त मोर्चा सरकार संघर्ष का औजार है। पूंजीपति और प्रतिक्रियावादी भयभीत हो गए थे। अन्य राज्यों में भी, इसका प्रभाव पड़ रहा था। इन पूंजीपतियों की सलाह से ही 1969 में दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन के दौरान, पूर्ववर्ती सरकार के लोकप्रिय मंत्री, कॉमरेड सुबोध बनर्जी को श्रम मंत्रालय से हटा दिया गया था और सीपीआई(एम) सहित दूसरों को आपूर्ति विभाग दिया गया था। अनिच्छा के बावजूद, हमारी पार्टी ने घोषित नीति को लागू करने के हित में इस मंत्रालय को अपनाया। इस संदर्भ में, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1977 में सरकार के गठन की पूर्व संध्या पर, सीपीआई(एम) नेता ज्योति बसु ने अपने दूसरे बेतार भाषण में कहा था कि 'उनकी सरकार में कोई अशांति अराजकता नहीं होगी, क्योंकि इस सरकार में एसयूसी को बाहर छोड़ दिया गया है'। उद्योगपतियों और प्रतिक्रियावादियों को इस कथन द्वारा आश्वासन दिया गया था। क्योंकि उनकी नजरों में आंदोलन, लड़ाई अशांति है, अराजकता है। हालांकि, पहली और दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकारों के शासनकाल में एक बड़ी पार्टी के रूप में सीपीआई(एम) पहले जितना वामपंथी राजनीति पर अमल किया करती थी और जन आंदोलन में भूमिका निभाती थी, अब उस रास्ते को दरकिनार करते हुए, एक तरफ तो पूंजीपतियों का विश्वास हासिल किया और दूसरी तरफ पुलिस-प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त मोर्चे में शामिल अन्य दलों पर हमले कर उनके प्रभावाधीन इलाकों पर कब्जा किया, आंदोलन की बजाय सुविधाए पाने की अवसरवादी राजनीति की ओर रुख किया, इससे उसने जनसमर्थन जुटाया और बेरोजगार नौजवानों को पार्टी में खींच लिया, बड़ी पार्टी का आधिपत्यवाद कायम किया, दूसरी पार्टियों की आवाज को दबाया, तरह-तरह के भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया। यह सब करते-करते और इस तरह अपना प्रभाव बढ़ाते-बढ़ाते संयुक्त मोर्चा सरकार की बजाय वर्ग आधारित फ्रन्ट का नारा देकर अपनी खुद की पार्टी की सरकार कायम करने की कुचेष्टा की। इस समय सीपीएम नेतृत्व एक तरफ तो अन्य वामपंथी दलों पर हमला कर रहा था और दूसरी तरफ नक्सली आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर भी हमले कर रहा था। इस प्रकार, पश्चिम बंगाल में वामपंथी आंदोलन में हत्या की राजनीति जारी रही। पश्चिम बंगाल के लोगों में जो कांग्रेस के खिलाफ वामपंथ से आकर्षित हुए थे, वामपंथी राजनीति के बारे में व्यापक हताशा और अनास्था बढ़ने लगी। वामपंथ की मर्यादा धूल में मिलती गई। उस समय यानी, 1968 में कॉमरेड शिवदास घोष ने जो चेतावनी दी थी, वह आज आपको याद दिलाना बहुत ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, "... इस स्थिति में जनसंघ जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी घात लगाए बैठे हैं। वे मौके का इंतजार कर रहे हैं। वामपंथी आंदोलन के प्रति लोगों का जो आकर्षण आज भी है, वह कम हो जाने पर ही वे खुद की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सत्तारूढ़ सीपीएम नेताओं को यह समझ में नहीं आता है। ...इस प्रकार साम्यवाद की प्रतिष्ठा को खत्म कर वे इस पर कालिख पोत रहे हैं।" आज इस चेतावनी का तात्पर्य कितना गहरा है, यह आप सभी और सीपीआई(एम) के ईमानदार कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझ लेना चाहिए।

बाद में, बड़े पैमाने पर धांधली के माध्यम से कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रॉय के नेतृत्व वाली सरकार बनी, उस सरकार ने सत्ता में आते ही हमारी पार्टी और सीपीआई(एम) और नक्सलियों पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जबकि कई लोगों को कत्ल किया गया। बहुत जल्दी यह सरकार अलोकप्रिय हो गई। इस बीच, कांग्रेस पूरे देश और पश्चिम बंगाल में बहुत अलोकप्रिय हो गई और पश्चिम बंगाल की जनता वामपंथियों की ओर झुक गई और सीपीआई(एम) को एक बड़ी पार्टी होने से इसका फायदा मिला। सन् 1977 के चुनाव में, सीपीआई(एम)-नीत फ्रंट ने जनता पार्टी के समर्थन से पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से सरकारी सत्ता पर कब्जा किया और लगातार 34 वर्षों तक शासन किया। इनके इस शासनकाल में, पुलिस-प्रशासन को पूरी तरह पार्टी की मुट्ठी में सरंक्षण देकर एंटीसोशल आतंक पैदा करने के काम में लगाया। स्कूल के चपरासी की भर्ती से लेकर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति तक, सभी पदों पर नियुक्ति, सरकारी कार्यालय में पदोन्नति, स्थानांतरण सभी कुछ दलगत स्वार्थ में और पार्टी के निर्देशन में किया गया। किसी आदर्श, नीति-सिद्धांत के जरिये नहीं, बल्कि प्रमोटरों, ठेकेदारों, बिल्डरों, हफ्ता वसूली करने वालों, रिश्वतखोरों, सिंडिकेटों को कमाई के अवसर आदि प्रलोभन देने के जरिये नौजवानों को दलबल के साथ पार्टी में शामिल किया गया। चुनावों में बार-बार बड़े पैमाने पर धांधली की और आतंक बरपाया, और लगभग सभी पंचायतों-नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लिया, इनको बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गुटबाजी के अखाड़े में तब्दील कर दिया। शिक्षा प्रबंधन के सभी स्तरों पर पार्टी का दबदबा कायम कर दिया। कॉलेज-विश्वविद्यालय के चुनावों में, पार्टी के छात्र संगठन, एसएफआई ने सभी विरोधियों पर हमले किये और एकतरफा तौर पर सभी यूनियनों पर कब्जा कर लिया। हर जगह हमलों, आतंक, जोर-जबरदस्ती, उखाड़ फेंकना, हर जगह खून-खराबा -यह सब पार्टी वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया। दूसरी ओर, बड़े पूंजीपतियों, बड़े व्यापारियों, बड़े भूस्वामियों के हित में श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन को दबाने के लिए फायरिंग कर मजदूर-किसानों को मार डाला। हमारी पार्टी मजदूर-किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों की मांगों के साथ-साथ प्राइमरी स्तर से अंग्रेजी शिक्षा सहित पास-फेल पुनः चालू करने, बसभाड़ा-किराया बढ़ोतरी वापस लेने आदि मांगों को लेकर कई आंदोलन गठित करती रही। सीपीआई(एम) ने नृशंसता के साथ लाठी-गोली चलायी, हमारी पार्टी के 171 नेता-कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या कर दी। झूठे मामलों में फंसा कर 51 नेताओं को आजीवन कारावास की सजा करवाई। सिंगुर-नंदीग्राम आंदोलन को दबाने के लिए भीषण अत्याचार किए। नंदीग्राम में पुलिस और असामाजिक तत्वों द्वारा बेरहमी से बलात्कार और नरसंहार किया गया। अपने तुच्छ दलगत स्वार्थ में ऐसी काली करतूतें करके, उन्होंने महान साम्यवाद और वामपंथ को जनमानस में बदनाम कर दिया। पश्चिम बंगाल के लोग सीपीआई(एम) से नाराज हो गए। इस मौके का फायदा उठा कर, पश्चिम बंगाल की कांग्रेस के अन्दरूनी सत्ता-संघर्ष, गुटबाजी और कलह के अंजाम के तौर पर बाहर निकल कर आई तृणमल कांग्रेस उभर कर सामने आयी और पूंजीपति वर्ग और मीडिया द्वारा सीपीआई(एम) के विकल्प के रूप में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में व्यापक प्रचार किया गया। सीपीआई(एम) के कुशासन से नाराज लोग बदलाव की मांग कर रहे थे और परिवर्तन का नारा देकर तृणमूल कांग्रेस चुनावों में भारी बहुमत से विजयी हुई।

लेकिन तृणमल कांग्रेस के शासन में क्या बदलाव आया? केवल सीपीआई(एम) पार्टी के बदले, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई -इसके सिवा क्या कोई और बदलाव आया है? सीपीआई(एम) के शासन के दौरान जिस तरह की काली करतूतें हुई थी, पुलिस-प्रशासन से लेकर हर जगह पार्टी का दबदबा कायम करना, चुनावों हर जगह धांधली-आतंक- जबरन चुनाव न लड़ने देना, असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल, हफ्ता वसूली, सिंडिकेट राज, हफ्ता वसूली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, विरोधियों पर हमले, जन आन्दोलनों पर दमन-उत्पीड़न आदि ये सब काली करतूतें इस शासन में भी सीपीआई(एम) की कार्बन कापी की तरह हो रही हैं। अंतर यह है कि, सीपीएम एक केन्द्रीकृत बंधी हुई पार्टी है, इसलिए सब कुछ सलीके से, विभिन्न स्तरों पर नेताओं के नियंत्रण में और बहुत बारीकी से होता है। जबकि तृणमूल कांग्रेस के शासन में वह मनमाने, खुले, नग्न, अराजक ढंग से होता है। क्योंकि इसमें हर कोई राजा है। इस तृणमूल शासनकाल में ही शारदा घोटाला, रोजवैली कांड, लाखों लोगों का सब कुछ लूट कर उन्हें तबाह कर दिया। हालांकि इसकी शुरुआत सीपीआई(एम) के शासनकाल में हुई थी। इन घोटालों और नारदा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के नाम जोड़े गए हैं। इसके अलावा, सरकारी राजस्व बढ़ाने के बहाने सरकार ने सीपीआई(एम) शासन के समय से दुगनी संख्या में शराब की दुकान खोल दी हैं। राह-घाट पर शराबियों का उत्पात पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। जो सरकार लड़कियों को सहायता राशि (कन्याश्री) बांट रही है, वह सरकार यह राज्य बलात्कार और महिलाओं की तस्करी का गढ़ बन जाने पर चूं तक नहीं कर रही है। हाल के लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित धक्का खाकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने अचानक नींद से जागकर यह पता लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग भारी रिश्वतखोरी का कारोबार कर रहे हैं। उसने इसके खिलाफ हुंकार भरी। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? फिर, इस सरकार ने क्या कुछ नया नहीं किया? बेशक किया है। जैसे कि कन्याश्री, युवाश्री, साइकिल दान, सैकड़ों क्लबों, पूजा समितियों, विभिन्न नाटक-यात्रा संस्थाओं को करोड़ों रुपये का दान, पूजा अनुष्ठान, मंदिर का जीर्णोद्धार, दूसरी ओर इमामों और मोअज्जमों का भत्ता, हिजाब पहनकर नमाज में शामिल होना, आदि जारी है। बाद में श्मशान के पुजारियों का भत्ता भी शुरू किया गया। विशेषज्ञ सलाहकारों को बाहर से बहुत सारे पैसे देकर लाया गया है ताकि वे अगले चुनावी वैतरणी को वैसे ही पार कर सकें। तृणमूल कांग्रेस पार्टी और सरकार काफी कुछ उनकी सलाह पर चल रही है। 'दीदी से कहो' नामक एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। लेकिन उससे भी वह पार्टी अंततः बच पाएगी या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा।

तृणमूल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार, जुल्म से नाराज होकर पश्चिम बंगाल में बहुत से लोग इस मानसिकता के साथ आरएसएस-बीजेपी के खाते में नाम लिखा रहे हैं कि इसे सबक सिखायेंगे। इनमें तृणमूल-कांग्रेस-सीपीआई(एम) के कुछ स्थानीय, जिला और राज्य स्तरीय छोटे और बड़े नेता शामिल हैं। अन्य राज्यों की तरह, इस राज्य में भी भाजपा ढेर सारे पैसों और नौकरियों का प्रलोभन देकर बेरोजगार युवाओं की भीड़ जुटा रही है। हवा के रुख को भांप कर सीबीआई-ईडी की सूची में भ्रष्टाचार के आरोप में तृणमूल कांग्रेस के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि और तृणमूल कांग्रेस के आश्रित गुण्डों का एक हिस्सा अब भाजपा में शामिल हो गया है। कई लोग शामिल होने के लिए लाइन में खड़े हैं। इसके जरिए आरएसएस-बीजेपी का बदन बढ़ रहा है। नेता बहुत खुश हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में उन्हें अप्रत्याशित वोट मिले, इसका उनको और भी ज्यादा हर्षोल्लास है। पश्चिम बंगाल के अगले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए तरह-तरह की रिहर्सल चल रही है।

वामपंथियों की कमजोरी ने की भाजपा की शक्ति वृद्धि में मदद

भाजपा को एक ही छलांग में अचानक इतने वोट और सीटें मिली हैं, क्या यह ऐसे ही हो गया है? क्या यह सिर्फ पैसों के बल पर और केंद्र में सरकारी सत्ता में होने की वजह से ही हुआ है?

(शेष पृष्ठ 6 पर)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-2020
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

कामरेड प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 5 का शेष)

मुकाबले में कम जरूर है, लेकिन तृणमूल ने भी पैसा खूब पानी की तरह बहाया है। तो यह कैसे संभव हुआ है? इसका जवाब कॉमरेड शिवदास घोष की उस चेतावनी में निहित है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। कांग्रेस के बाद सीपीआई(एम) के लंबे शासन ने पश्चिम बंगाल में पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन की क्रांतिकारी परंपराओं को मलियामेट कर दिया और सर्वोपरि, साम्यवाद और वामपंथ की गरिमा को बट्टा लगा दिया। अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस के बदले में भाजपा को वोट दिये जाते हैं, भाजपा के बदले कांग्रेस को वोट दिये जाते हैं या अन्य क्षेत्रीय दलों को, इस तरह उलटफेर होती है, लेकिन इस राज्य में सीपीआई(एम) आज इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि 2011 में सत्ता से हटाये जाने के बाद भी इसके कार्यकर्ताओं-समर्थकों की ताकत में संगठन के विस्तार में वोट के हिसाब से प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद, पश्चिम बंगाल के लोगों ने अभी भी तृणमूल कांग्रेस के विकल्प के रूप में सीपीआई(एम) को नहीं अपनाया है, आरएसएस-भाजपा को अपनाया है। क्या सिर्फ ऐसी बात है? सीपीएम के 28 प्रतिशत वोट घटकर 7 प्रतिशत रह गए। ध्रुवीकरण हो जाने के मद्देनजर, निचले तल्ले परं सीपीआई(एम) के हिंदू और मुस्लिम कार्यकर्ता-समर्थकों, कई स्थानीय नेताओं के एक धड़े ने भाजपा, दूसरे धड़े ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया। गांवों में भी, शहरों के मौहल्ले-मौहल्ले में आम लोगों ने ही साफ देखा है कि सीपीआई(एम) के कई लोग इस तर्क के साथ भाजपा का समर्थन कर रहे हैं कि अब राम आएंगे, फिर वामपंथी आएंगे। यानी अब तृणमूल कांग्रेस को हरा कर बीजेपी जितेगी, तो बाद में मानो सीपीआई(एम) बीजेपी की जगह ले लेगी। ऐसा भी हुआ कि कुछ केंद्रों में, सीपीआई(एम) पार्टी के पोलिंग एजेंटों तक ने सीपीआई(एम) के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। क्या नेता आत्म समीक्षा न करके इसके लिए निचले दर्जे के कार्यकर्ताओं को दोष देकर अपने दायित्व से बच सकते हैं? क्या इसके लिए नेतृत्व और पार्टी की नीतियां जिम्मेदार नहीं हैं? क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल में बहुत रक्त बहाकर और बलिदान देकर बदले में निर्मित हुई वामपंथ की साख को बड़ी पार्टी होने के नाते भुना कर लम्बे अर्से तक सरकारी सत्ता में बैठे रहते हुए वर्ग संघर्ष और जन आंदोलन को ध्वस्त नहीं किया? क्या वामपंथ की गरिमा मिट्टी में नहीं मिला दी है? क्या कार्यकर्ताओं को वामपंथी राजनीति से विमुख और संस्कृति रहित करके सुविधावाद के दलदल में नहीं डुबोया? क्या उन्नत नैतिकता हासिल करने की मानसिकता को नष्ट करके असामाजिकता के द्वारा युवा समाज का नैतिक पतन नहीं किया गया? विचारधारा-चरित्र-संघर्ष नहीं, बल्कि सरकारी सत्ता ही शक्ति का स्रोत है -क्या कार्यकर्ताओं में यह मानसिकता तैयार नहीं की गई? यदि हमारा यह आरोप गलत है, तो सीपीआई(एम) नेतृत्व सही जवाब दे, हम मान लेंगे कि हमारा आरोप गलत था। मैं ये बातें किसी दुश्मनी से नहीं कह रहा हूं। बल्कि इस चिंता से कह रहा हूं कि इस राज्य में जिस वामपंथी धारा को ब्रिटिश सरकार और बाद में कांग्रेस सरकार बहुत अधिक लाठी-गोली चला करके भी नष्ट नहीं कर सकी, वह काम सीपीआई(एम) ने सरकारी सत्ता में बैठ कर दिया। यदि वे वामपंथी धारा में सरकार चलातें, तो 34 साल सरकार चलाने के बाद उनकी शक्ति तो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती -जबकि उल्टे, क्या हुआ? सीपीआई(एम) के ईमानदार कार्यकर्ता और समर्थक हमारी आलोचना को ठण्डे दिमाग से सोचविचार करके देखें-परखें क्योंकि एक दिन आप साम्यवाद की ओर आकर्षित होकर इस पार्टी में शामिल हुए थे। अतीत में, आपमें से पहले कई लोग शहीद, प्रताड़ित और अत्याचारित हुए हैं। लेकिन आज इसका परिणाम क्या हुआ? आप 'मार्क्सवाद जिंदाबाद' का नारा सुनकर और पार्टी का जनाधार देखकर इसमें शामिल हुए थे। बारीकी से सोच कर नहीं देखा कि पार्टी की विचार पद्धति, राजनीतिक विश्लेषण, कार्यक्रम, रणनीति, रणकौशल, आचरण- व्यवहार, संस्कृति, नेताओं की जीवन शैली, चाहे मार्क्सवादसम्मत हो, या नहीं।

क्या राज्य में तृणमूल से बेहतर सुशासन देगी भाजपा?

क्या पश्चिम बंगाल की जनता का जो तबका भ्रष्टाचार बंद करने, दमन-उत्पीड़न को रोकने, लोकतंत्र को बहाल करने आदि के लिए भाजपा को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहा है, क्या उसने देखा है कि भाजपा शासित राज्यों और केंद्रों में वह कैसे सरकार चला रही है? जब बीजेपी सरकार में थी, तब करोड़ों रुपये डकार कर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या विदेश कैसे भाग सके थे? इस भ्रष्ट नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री तस्वीर में क्यों दिखाई दिये और उनकी मुलाकात क्यों हुई? भाजपा के शासनकाल में भाजपा अध्यक्ष और उनके पुत्र ने इतनी संपत्ति कैसे बढ़ा ली? मध्य प्रदेश में, भाजपा शासनकाल में 30 हजार करोड़ रुपये का व्यापम घोटाला हुआ - जिसमें लाखों रुपये के बदले में सरकारी नौकरी, पदोन्नति, और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के भ्रष्टाचार में भाजपा के मंत्री संलिप्त थे, इस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए कथित रूप से 48 गवाहों का रहस्यमय ढंग से खून कर दिया गया है। आज इस भ्रष्टाचार और हत्या की जांच क्यों नहीं? दोषियों को सजा क्यों नहीं दी जाती? बोफोर्स जैसे राफाल विमान घोटाले की जांच को क्यों दबाया गया?

जम्मू के कठुआ में अल्पसंख्यक समुदाय की बालिका के 8 बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा करने और सजा नहीं देने की मांग करने के लिए भाजपा के दो मंत्रियों चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने जुलूस क्यों निकाला था? मुकदमा वहां की अदालत की बजाय बाहर के राज्य की अदालत में क्यों लाया गया? इसी तरह, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, 2017 में जिस लड़की से बलात्कार हुआ, उसकी एफआईआर तक पहले पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की गई, उसके पिता पुलिस स्टेशन गए और झूठे इल्जाम में फंसा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 2018 में बलात्कार पीड़िता मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने गई और अंततः पुलिस बलात्कारी को गिरफ्तार करने पर मजबूर हुई। क्योंकि बलात्कारी सत्तारूढ़ भाजपा का विधायक है। बलात्कार पीड़िता और उसका वकील हाल ही में करवाई गई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये थे और उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। तब जाकर इतने दिनों बाद, भाजपा उस विधायक को पार्टी से निष्कासित करने के लिए मजबूर हुई है। सन् 2014 से ही भाजपा के शासन में पीट-पीट कर हत्या कर देना एक नियमित घटना बन गई है। फर्जी मुठभेड़ों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में सरकार द्वारा दुखियारी महिलाओं के आश्रयस्थलों, 'होम' यानी घरों में सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार, महिलाओं की तस्करी और हत्या की घटनाओं की खबर आई है। 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के गवाह तुलसीराम प्रजापति की 2006 में हत्या कर दी गई थी। बीजेपी अध्यक्ष भी इस हत्या के आरोपियों में शामिल थे। न्यायाधीश लोया ने उन्हें 2014 में 15 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया था, क्योंकि मुकदमा चलने के दौरान पेशी पर वे बार-बार अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद 1 दिसम्बर को जस्टिस लोया की रहस्यमय हालात में मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने शिकायत की कि यह हत्या थी और पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लोया को रिश्वत की पेशकश की गई थी जिसके लिए वे सहमत नहीं हुए थे। लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। इस मामले में सीबीआई द्वारा सबूत पेश करने में विफल रहने पर, अगले न्यायमूर्ति एस जे गर्ग ने आरोपी को कोई भी सजा देने में विफल रहने के लिए सोहराबुद्दीन परिवार से माफी मांगी। भारत में, इस तरह अंतरात्मा के कचोटने से व्यथित न्यायाधीश द्वारा माफी मांगने की घटना इससे पहले कभी नहीं घटी। उन्होंने समझ लिया था कि दोषियों को सजा नहीं मिल पाये इसका बंदोबस्त सीबीआई ने कर लिया था। इसी तरह, न्यायमूर्ति जगदीप सिंह समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट करने की साजिश में आरोपित स्वामी असीमानंद सहित सभी आरोपियों को सजा नहीं दे सके क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पुख्ता सबूत पेश नहीं किये। परेशान और हैरान, जज जगदीप सिंह ने अपने फैसले में कहा, 'मुझे गहरे दर्द और पीड़ा के साथ फैसले का समापन करना पड़ रहा है क्योंकि विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्यों के अभाव की वजह से इस जघन्य अपराध में किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सका. अभियोजन के साक्ष्यों में निरंतरता का अभाव था और आतंकवाद का मामला अनसुलझा रह गया.' क्या भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने पर न्याय दिलाएगी?

क्या पश्चिम बंगाल के लोग इस भाजपा से भ्रष्टाचार मुक्त, लोकतांत्रिक, उत्पीड़न मुक्त शासन की उम्मीद कर सकते हैं? पहले से ही, सीबीआई-ईडी खाते में कई आरोपियों की भाजपा में भीड़ लगी हुई है, क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई को मजबूत करना है? विधानसभा चुनावों में तो अभी भी बहुत देर है, पहले से ही तृणमूल कांग्रेस-भाजपा के लड़ाई-झगड़े, हत्याएं चल रही हैं, क्या इनके लिए केवल तृणमूल कांग्रेस ही जिम्मेदार है, भाजपा नहीं? क्या यह भाजपा इस राज्य में सुशासन और शांति स्थापित करेगी? इस राज्य में अल्पसंख्यकों को इस बीच 'जय श्री राम' कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उत्पीड़न शुरू हो गया है। क्या यह वास्तव में ईमानदारी से धर्मप्रचार है या गुण्डागर्दी? यह सरकारी सत्ता मिल जाने से इससे भी ज्यादा बढ़ता ही रहेगा। इसकी उल्टी प्रतिक्रिया के तौर पर, यदि बांग्लादेश में हिंदुओं को 'अल्लाहो अकबर' कहलाना और न कहने पर उनके साथ मारपीट करना शुरू हो जाए, तो क्या आप इसे गुण्डागर्दी कहेंगे या धर्मप्रचार?

जो लोग आरएसएस-बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं, क्या उन्होंने सोच-विचार कर देखा है कि यह आरएसएस-भाजपा ही राममोहन-विद्यासागर पुनर्जागरण की परंपरा को ध्वस्त करके एक मध्यकालीन धर्मान्ध अंधकारमय माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है? क्या वे ऐसा होने देंगे?

क्या उन्हें लगता है कि इस आरएसएस -भाजपा ने ही तो स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बहादुर योद्धाओं और शहीद देशबंधु-बिपिन पाल-सुभाष चंद्र-खुदीराम-सूर्य सेन- प्रीतिलता -बाघा जतिन को 'प्रतिक्रियावादी' और 'देशद्रोही' करार दिया था और उनकी संग्रामी विरासत को धार्मिक उग्रता भड़का कर मिटा देने की साजिश रच रही है? क्या वे चाहते हैं कि ऐसा हो?

क्या उन्होंने गौर किया है कि चैतन्य-रामकृष्ण-विवेकानंद जिस हिंदू धर्म का प्रचार कर गए हैं, आरएसएस-भाजपा द्वारा प्रचारित हिन्दुत्व उस प्रचार का पूर्णतः विरोधी है। जिसका एकमात्र उद्देश्य धार्मिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने का स्वार्थ सिद्ध करना है।

पश्चिम बंगाल के लोगों को एक और बात सोचने की जरूरत है कि उन्होंने पहले कांग्रेस को एक अंधे की तरह समर्थन दिया, फिर कांग्रेस के शासन से आजिज आकर कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सीपीआई(एम) को आँख बंद करके जिताया, बाद में सीपीआई(एम) के अत्याचार-उत्पीड़न से परेशान होकर सीपीआई(एम) को सबक सिखाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को अंधे की तरह समर्थन दिया। अब फिर एक तबका तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जुल्मो-सितम से नाराज होकर तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भाजपा को अंधे की तरह समर्थन देकर जिताने की सोच रहा है, इसके बाद किसे जिताओगे? क्या यह खेल बार-बार चलता रहेगा? क्या इससे चहुंदिशाओं में प्रगति हो रही है, या दिन-ब-दिन गिरावट और भी बढ़ रही है? बार-बार, उनमें से कोई न कोई स्वर्ग राज्य कायम कर देने का राग अलापते हुए चुनाव में जीत रहा है। लेकिन क्या जनसाधारण जीत रहे हैं, या दुर्गति की चरम को पार कर रहे हैं?

मुख्य दुश्मन पूंजीवाद को पहचानें

ये सभी दल पाखंडी हैं, धोखेबाज हैं। लेकिन याद रखें, यदि आप एक ईमानदार पार्टी खोज पाते हैं और उस पार्टी को भी यदि जिता देते हैं, फिर भी जब तक पूंजीवादी शोषण-शासन बरकरार है, तब तक बेरोजगारी, छंटनी, मूल्य वृद्धि, भुखमरी, बिना उपचार मृत्यु, भ्रष्टाचार, महिलाओं और बच्चियों की तस्करी, बलात्कार और हत्याएं जारी ही रहेंगी, बढ़ती ही रहेंगी। आज पूंजीवाद घोर प्रतिक्रियावादी, दमनकारी है। उसका एकमात्र लक्ष्य अत्यधिक मुनाफा कमाना है, श्रम का अत्यधिक शोषण करना उसके हित में है। शोषित लोगों की क्रय शक्ति लगातार सिकुड़ती जा रही है, इसलिए बाजार सिकुड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक-निजी उद्योगों और कार्यालयों में लाखों पद रिक्त पड़े होने के बावजूद कारखानें बंद हो रहे हैं, छंटनी-लेऑफ बढ़ रहा है, नई भर्ती को बंद किया जा रहा है, अनुबंध आधारित काम कराया जा रहा है जहां काम का समय सर्वाधिक है, लेकिन मजदूरी बहुत कम है। मालिक जब चाहे मजदूरों को नौकरी से हटा सकता है, कारखाने को बंद कर सकता है, लेकिन मजदूरों के प्रतिवाद करने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार छीन लिया जा रहा है। विश्व साम्राज्यवाद-पूंजीवाद बाजार हासिल करने के लिए, अन्य देशों को लूटने के लिए हमला कर रहे हैं, युद्ध थोप रहे हैं, लाखों लोगों को मार रहे हैं, उन्हें बेघर कर रहे हैं, विनाशलीला कर रहे हैं। वैश्विक साम्राज्यवाद-पूंजी बाजार संकट आज इतना तीव्र है कि साम्राज्यवाद के सरगना, जिस संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ समय पहले विश्व बाजार को हथियाने के लिए वैश्वीकरण की योजना शुरू की थी, वह आज प्रतिस्पर्धा में पिट करके वैश्वीकरण के खिलाफ बोलने लगा है। साम्राज्यवादी चीन के साथ उसका ट्रेड वार यानी व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। यह भी एक प्रकार का युद्ध है, वैसा ही जैसा कि बोलचाल की भाषा में कहावत है हाथ से नहीं मारना, बल्कि भात से मार देना। इस युद्ध में, भारत सहित सभी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश लिप्त हैं। पूरी दुनिया की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मंदी की मार से तबाह है। परिणामस्वरूप, लाखों कारखाने बंद हो जाएंगे और करोड़ों श्रमिकों की छंटनी होगी।

पूंजीवाद के मुनाफे का लालच इतना प्रबल है कि मूल्यों, मानवीयता, मानव सभ्यता के हितों का उसकी नजरों में कोई मूल्य नहीं है। इसलिए, वैज्ञानिक बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि जीवाश्म तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, आदि के उद्योगों में बढ़ते इस्तेमाल के कारण ग्रीनहाउस गैसें बढ़ रही हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मायण और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के ढेरों के

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कामरेड प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 6 का शेष)

पिघलने से समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी धरती के स्थल भाग के लिए खतरा पैदा कर रही है। प्राकृतिक परिवेश भी संकट में है। जलवायु में खतरनाक बदलाव आ रहा है। फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी राज्य, पूंजीपतियों के हित में किसी की नहीं सुन रहा है। मानव जाति का चाहे कितना भी विनाश क्यों न हो, उन्हें अपना मुनाफा बढ़ाने की पड़ी है। यह पूंजीवाद मानव जाति का परम शत्रु है।

याद रखें, यह पूंजीवाद है जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण-शासन के बदले भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा होने वाला शोषण -शासन चलाया हुआ है। यही नहीं, भारतीय पूंजीवाद, एकाधिकार पूंजी और बहुराष्ट्रीय पूंजी को जन्म देने के साथ साम्राज्यवादी बन कर, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि अमेरिका और यूरोप में भी पूंजी निवेश के उद्योग लगा रहा है, व्यापार-वाणिज्य कर रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद - जापान के साथ आर्थिक और सैन्य समझौते करके भारत महासागरों सहित उपमहाद्वीप पर अपने आधिपत्य का विस्तार कर रहा है। कांग्रेस लंबे समय से इसी पूंजीवाद की वफादार सेवक रही है, और आज भाजपा उस कार्य में लगी हुई है। और देश ने क्या प्रगति की है? लगभग 63 करोड़ भारतीय बेरोजगार हैं, पिछले दो वर्षों में दो करोड़ श्रमिकों की छंटनी की गई है, भुखमरी के मामले में दुनिया के 119 देशों में भारत का स्थान 107वां है, 62 प्रतिशत भारतीय बहुत गरीब हैं, 67 करोड़ भारतीयों के पास 1 प्रतिशत धन-दौलत है, प्रतिदिन 23 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, प्रतिदिन 7 हजार लोग भुखमरी और बेइलाज मर जाते हैं, प्रति घंटे 5 किसान-मजदूर आत्महत्या करते हैं, पिछले कुछ वर्षों में 3 लाख 50 हजार किसानों ने आत्महत्या की है, शिशु मृत्यु, नारी भ्रूण हत्या, महिलाओं और बच्चों की तस्करी, और महिलाओं से बलात्कार में भारत दुनिया में अग्रणी है।

जबकि कुछ दिनों बाद, 15 अगस्त को करोड़ों रुपये खर्च कर बड़े आडम्बर के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सुबह तोपों की सलामी, फौजी परेड, झंडा फहराने के साथ होगा - देश के विकास के रंगीन सब्जबाग दिखाने के साथ प्रधानमंत्री का भाषण होगा, शाम को राष्ट्रपति भवन, राजभवन, फाईव स्टार प्रसिद्ध होटलों में एक बहुत महंगा भोज होगा, झिलमिलाती रोशनियों से आलोकित किया जाएगा और उस आनन्दोत्सर्व में नेता, मंत्री, उद्योगपति, बड़े-बड़े व्यापारी शामिल होंगे। जबकि उसी समय दूसरी तरफ एक गहरे अंधकार से घिरी तस्वीर देखने को मिलेगी। यह देखा जा सकता है कि लाखों फुटपाथवासी मानव संतानें डस्टबिन से भोजन संग्रह कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके माता-पिता कहां हैं, उनका पता-ठिकाना कहां है सैकड़ों भूखे असहाय लोग सिसक रहे होंगे, उनके चुपचाप आंसू बहेंगे। कितनी भी मजदूरी के लिए काम की तलास में मारे -मारे फिरते, दर-दर भटकते लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर होंगे, एक नये-नये छंटनी हुए मजदूर-कर्मचारी की आत्महत्या, कितनी शोकाकुल माताएँ बेइलाज मरे अपने बच्चे को गोद में लिए हाहाकार करती होंगी, और सैकड़ों असहनीय गरीबी से ग्रसित मां-बाप अपने बच्चों को, कन्याओं को बेच रहे होंगे। देखने को मिलेगा कि गली-मौहल्ले, स्टेशन, राह-घाट पर देह व्यापार की मण्डी में परिवार के अस्तित्व को बचाने के सभी सुयोग-सुविधाओं से वंचित हजारों असहाय महिलाएं खड़ी होकर खरीददार को तलाश रही हैं। और बलात्कार की कई चीखें सुनाई देंगी। इन करोड़ों भारतीयों के लिए, जो सोचते हैं, 'मेरा मर जाना ही बेहतर है, कम से कम मुझे यह दर्द तो सहन नहीं करना पड़ेगा', उनके लिए 15 अगस्त अज्ञात है, वे इससे अपरिचित हैं और अन्य दिनों की तरह ही वह दु:खमय है। आजादी के जिस सपने को लेकर, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम ने फांसी के तख्ते पर चढ़कर अपनी जान की आहूति दी थी, और फिर भगत सिंह, सूर्य सेन, प्रीतिलता, चंद्रशेखर आजाद सहित सैकड़ों अन्य लोग शहीद हो गए थे, क्या उन्होंने दु:स्वप्न में भी स्वतंत्र भारत की इस दुखद असहनीय तस्वीर को सोचा था?

सोवियत समाजवाद में हुआ एक नई सभ्यता का सूर्योदय

क्या उन्होंने सोचा था कि पूँजीपति वर्ग और शासक दलों की साजिश से एक दिन, पुनर्जागरण के मनीषियों, वीर स्वतंत्रता सेनानियों, इस देश के शहीदों की याद को भुला कर इस देश के छात्र-नौजवानों को जुए-सट्टे-दारू-नशे-अश्लील फिल्म-गंदे सेक्स के गर्त में डुबो दिया जाएगा? ज्ञान-विज्ञान-साहित्य की प्रगति रुक जाएगी, इन्सानियत, मानवीय मूल्य, रूचि-संस्कृति, स्नेह-प्रेम-प्यार सब कुछ मिट जाएगा और घोर व्यक्ति केन्द्रीकता, खुदगर्जी पारिवारिक जीवन-सामाजिक जीवन को नष्ट कर देगी? किसी भी तरह से, पैसा कमाना, गंदा भोगविलासपूर्ण जीवन का मूल मंत्र बन जाएगा? एक विवेकहीन, मनुष्यत्वरहित, नशे में चूर मानव देहधारी युवा कुत्सित कामवासना पूरी करने के लिए गाँव-शहरों में, निर्जन घरों में सैकड़ों नन्ही बच्चियों से लेकर बुढ़ी औरतों तक से बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे? शिक्षक, जन्म देने वाले पिता तक पर यह आरोप लगाया जाएगा? यह कौन सी सभ्यता है? आदिम समाज में, पशुजगत में भी ऐसी बर्बरता नहीं होती। ये पशु से भी नीच किस्म की हरकतें सिर्फ इस देश में ही नहीं, बल्कि सभी साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों में आज कमो-बेश होती हैं। यह पूंजीवाद मानव जीवन में अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, ज्ञान साधना, रूचि-संस्कृति सब कुछ नष्ट कर रहा है। यह पूंजीवाद मानव सभ्यता का घोर शत्रु है। इसलिए इसे केवल 5 वर्षों के बाद एकदिन बटन दबा कर कभी इस और कभी उस पार्टी को चुनावों में जिताने से इस दुस्सह चौतरफा संकटमय जीवन से निजात नहीं मिलेगी। इसलिए, पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति चाहिए।

विश्व साम्राज्यवादी-पूंजीवादी व्यवस्था में जब बीसवीं सदी की शुरुआत में हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, तब महान मार्क्सवादी विचारक लेनिन के नेतृत्व में रूस में हुई समाजवादी क्रांति से नई सभ्यता का सूर्योदय हुआ था, जिसका पाश्चात्य देशों के मनीषियों रोमां रोलां, आइन्स्टाइन और हमारे देश के रवींद्रनाथ, शरत चन्द्र, प्रेमचंद, नजरूल, सुब्रह्मण्यम भारती, ज्योतिप्रसाद अग्रवाल, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह व अन्य कइयों ने मुग्धचित्त से अभिनन्दन किया था। सभी प्रकार के शोषण से मुक्त इस समाजवादी सभ्यता ने रवींद्रनाथ के शब्दों में, पहले पहल स्वतंत्रता-समानता-बंधुता के संदेश को वास्तविकता में बदल दिया था। 'लोगों द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए' के नारे को साकार कर दिखाया था। इस 'लोगों' का मतलब है मेहनतकश लोग, न कि शोषक वर्ग। पूंजीवादी देश में मुट्ठी भर बुर्जुआ कानूनविदों, बुद्धिजीवियों ने संविधान लिखा था। जबकि समाजवादी रूस में, संविधान लाखों मेहनतकश लोगों के सक्रिय और प्रत्यक्ष विचारों के आधार पर लिखा गया था। जहां पूंजीवादी देश में मुख्यत: अमीर लोग ही चुनावों में उम्मीदवार खड़े होते हैं, वहीं समाजवादी रूस में, चुनावों में अधिकांश केंद्रों में उम्मीदवार होते थे - मजदूर, किसान, मुट्ठी भर सीटों पर बुद्धिजीवी और सैनिकों के प्रतिनिधि। निर्वाचित उम्मीदवारों को मतदाताओं को नियमित रिपोर्ट देना आवश्यक था। उनका काम पसंद नहीं आने पर किसी भी समय, मतदाता नए प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे। वापस बुलाने का यह अधिकार किसी पूंजीवादी देश में नहीं है। जहां पूंजीवादी देशों में उत्पादन का मुख्य लक्ष्य मालिकों के द्वारा अधिकधिक मुनाफा कमाना है, वहीं सोवियत समाजवाद में उत्पादन का मुख्य लक्ष्य जनता की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करना था। वहां बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। कोई छंटनी नहीं थी। सभी को काम करने का अधिकार था। उत्पादन से जो आय होती थी, उसका एक हिस्सा कारखाने समिति द्वारा ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करके श्रमिकों की वित्तीय मजदूरी के रूप में दिया जाता था और दूसरा हिस्सा सामाजिक मजदूरी के रूप में राज्य को दिया जाता था। राज्य इस आय से नि:शुल्क सार्वजनिक शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं, खेल-कूद प्रशिक्षण और सभी के लिए समुद्र तटों और पहाड़ों पर सेनेटोरियम व स्वास्थ्य आवास, बच्चों के लिए नर्सरी और किंडरगार्टन, बुजुर्गों और विकलांगों की देखभाल के लिए सहुलियतें मुहैया कराता था। राज्य इस आय से मुफ्त बिजली, ईंधन, जल, परिवहन और परिधान श्रमिकों को प्रदान करता था, वे कम किराए में घरों और मामूली सी कीमतों पर भोजन और अन्य कपड़े प्राप्त कर सकते थे। साप्ताहिक अवकाश के अलावा स्वास्थ्य आवास में रहने के लिए श्रमिकों को साल में 15 दिन की सवेतन छुट्टियां भी मिलती थी। महिला कर्मचारियों को वेतन के साथ डेढ़ साल का मातृत्व अवकाश मिलता था, फिर वे अपने बच्चों को सरकारी खर्च पर क्रेच में रखकर काम कर सकती थी। काम का समय पहले 8 घंटे रोजाना था, फिर 7 घण्टे हुआ, इसके बाद 6 घंटे और उसके बाद 5 घण्टे करने का सुझाव स्टालिन ने अपनी मृत्यु से पहले दिया था। सरकारी खर्च पर, मजदूर-किसानों की विश्वस्तरीय साहित्यिक गतिविधियों और सांस्कृतिक मनोरंजन के उद्देश्य से शहरों और गांवों में हजारों पुस्तकालय-थिएटर स्टेज-सिनेमा हॉल बनाए गए थे। शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, डॉक्टरों, वकीलों आदि सभी पेशेवर लोगों को अलग से रोजगार की आवश्यकता नहीं थी, राज्य ने उनकी जिम्मेदारी ले रखी थी। अदालत में इन्साफ चाहने वाले को किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं उठाना पड़ता था, राज्य सारा खर्च वहन करता था। बाकी पैसा राज्य वैज्ञानिक अनुसंधान और नई खोजों, नई दवाओं की खोज, उद्योग और कृषि के विकास के लिए नई तकनीकों की खोज, प्रशासनिक कार्य और सेना की ताकत बढ़ाने पर खर्च किया करता था। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि क्रांति के बाद, रूस ने प्रस्ताव दिया था कि सभी राष्ट्रों को पूर्ण निरस्त्रीकरण कर देना चाहिए, ताकि युद्ध के डरावनी विनाशलीला से मुक्त दुनिया अपना सारा पैसा जनकल्याण पर खर्च कर सके। साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देश इससे सहमत नहीं थे। यूरोप के सबसे अविकसित देशों में से एक, रूस एक समय मार्क्सवाद की मदद से दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक बन गया था- जहां गरीबी, भुखमरी, बेइलाज मृत्यु, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति ये सब बिल्कुल खत्म हो गई थी। ज्ञान-विज्ञान-साहित्य-संस्कृति का व्यापक विस्तार हुआ था। धार्मिक-नस्लीय बैरभाव का खात्माा हो गया था। विश्व ओलंपिक में शीर्ष पर समाजवादी रूस का कब्जा था। विज्ञान में इतनी प्रगति हुई कि समाजवादी रूस ने कई नई दवाओं का आविष्कार किया, मानव को अंतरिक्ष में भेजा और 12 सोवियत वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।

यह समाजवादी रूस ही सभी देशों के आजादी आंदोलन और मुक्ति संघर्ष का केंद्र था, जो विश्व शांति का सजग प्रहरी था। स्टालिन की अगुवाई में इस समाजवादी रूस ने ही द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी-इटली की फासीवादी ताकतों और साम्राज्यवादी हमलों से दुनिया की रक्षा करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, और रोमां रोलां, रवींद्रनाथ सहित दुनिया के सभी मानवतावादियों ने इस मामले में सिर्फ समाजवादी रूस पर ही भरोसा जताया था। विश्वविख्यात बर्नाड शा ने कहा था, ''दुनिया में आजादी व लोकतंत्र एक ही देश में है, वह है सोवियत यूनियन, जहाँ महान स्टालिन जिन्दा है।'' दूसरे विश्व युद्ध से पहले, हर प्रकार के शोषण-दमन से मुक्त समाजवादी रूस की इस नई सभ्यता के चरित्र और इसकी जबरदस्त प्रगति देखकर भगत सिंह ने फांसी से पहले खुद को मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट घोषित किया था। सन् 1939 में में पुरुलिया के अभिनन्दन सम्मारोह में बोलते हुए, सुभाष चंद्र ने कहा, 'दुनिया की वर्तमान स्थिति में, कई धाराओं और प्रतिधाराओं को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लम्बे डग भरती साम्यवादी ताकतें हैं, इसलिए हिटलरशाही के अंत का मतलब है साम्यवाद की स्थापना।' द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद, 1945 में नेताजी ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से घोषणा की, "जोसेफ स्टालिन अभी भी जीवित है, यूरोप और दुनिया का भविष्य अगले दिनों में उस पर निर्भर करेगा।" बहुत ही अभिभूत होकर रवीन्द्रनाथ ने 1939 में लिखा था, "नाना त्रुटियों के बावजूद मानव के नवयुग के रूप इस तपोभूमि को देखकर में आनन्दित और आशान्वित हुआ हूँ, मानव इतिहास में आनन्द और आशा का स्थायी कारण और कहीं नहीं देखता हूँ, जानता हूँ एक बड़ी भारी क्रान्ति के ऊपर ही रूस ने इस नये युग को कायम किया है। लेकिन यह क्रान्ति इन्सान के सबसे निष्ठुर और प्रबल दुश्मन के खिलाफ क्रान्ति है—यह क्रान्ति अनेक दिनों के पापों के प्रायश्चित का विधान है, ...नवजात रूस मानव सभ्यता के अस्थिपिंजर से मृत्यु की एक बड़ी शिला को हटाने की साधना कर रहा है, जिसे लोभ कहते हैं। अपने आप प्रार्थना निकलती है कि वे इस साधना में सफल हों।"

यह बड़े अफसोस की बात है कि इतनी सफलता के बावजूद, विश्व साम्राज्यवाद और रूस-चीन के भीतर उखाड़ फेंके गए पराजित पूंजीवाद ने बड़ी गुपचुप साजिश रची और आखिरकार संशोधनवाद के रास्ते प्रतिक्रान्ति कर दी, खतरे में पड़ गई मानव जाति के आशा-उम्मीद, भरोसे के केन्द्र रूस और चीन में मजदूर वर्ग द्वारा निर्मित समाजवादी व्यवस्था को ढहा दिया। लेकिन जो लोग मानव सभ्यता के इतिहास को जानते हैं, उन्हें निराश होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि किसी भी विचारधारा की अंतिम जीत के लिए, सैकड़ों वर्षों तक जीत-हार-जीत का रास्ता तय करना पड़ता है। जिस धर्म को ईश्वरीय वाणी कहा जाता है, उस हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म के मामले में भी ऐसा हुआ है। बुद्ध के उपदेशों को बौद्ध धर्म कहा जाता था लेकिन वे नास्तिक थे। इस बौद्ध धर्म के प्रभाव से वैदिक हिंदू धर्म परास्त हो जाने पर सैकड़ों वर्षों तक कोने में दुबका पड़ा रहा था, देवी-देवताओं की पूजा, पशु बलि, ब्राह्मणवाद का बोलबाला लगभग बंद हो गया था। लेकिन फिर से शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से बौद्ध धर्म को हराकर हिंदू धर्म प्रतिष्ठित कर दिया। यूरोप में राजशाही-विरोधी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में पुनर्जागरण से शुरू होकर, जीत-हार के रास्ते पर अंतिम जीत हासिल करने में 350 साल लग

(शेष पृष्ठ 8 पर)

भूल सुधार

सर्वहारा दृष्टिकोण, वर्ष 34, अंक-16, में पृष्ठ 7 पर 'गोशालाओं में मर रही हैं गाय' लेख में 125 गाय लिखा गया था। इसकी बजाय 1200 गाय और पृ. 4 कालम 2 न. 4 पर श्रीनगर की बजाय देहरादून पढ़ें। अनजाने में हुई इस गलती के लिए हमें खेद है।—सम्पादक, स. दृ.

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 of every month, Fortnightly, Date of Publication : Sep 5, 2019

कामरेड प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 7 का शेष)

गए थे। इस पैमाने से, 60/70 साल के समाजवाद की जीत की मियाद थी ही कितनी और धार्मिक आंदोलन की, बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति तो कोई शोषण उखाड़ फेंकने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरह के शोषण की जगह, दूसरी तरह का शोषण, यानी दासप्रथा की जगह राजतंत्र, राजतंत्र के बदले पूंजीवाद कायम हुआ था। जबकि समाजवाद को हजारों वर्षों के वर्ग शोषण के खिलाफ लड़ना पड़ा है। मैंने पहले भी विभिन्न सभाओं में ये बातें कही हैं, इस कारण से कही हैं कि बहुत से लोग अभी भी समाजवाद को लेकर हताशा-निराशा में डुबे हुए हैं, उन्हें लगता है कि समाजवादी क्रांति नहीं होगी, या हो भी गई, तो नहीं टिक पाएगी। यह सोच ऐतिहास और विज्ञानसम्मत नहीं है। शोषित जनता फिर से सीना तान कर उठ खड़ी होगी। क्रांतिकारी पार्टी और क्रांतिकारी नेतृत्व निर्मित हो जाएगा और देश-देश में समाजवादी क्रांति होगी वरना, मानव सभ्यता का भविष्य क्या है? जन जीवन का यह भयानक संकट जारी रहेगा, बढ़ता ही रहेगा।

महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष का शानदार संघर्ष

इस समाजवादी क्रांति को सफल बनाने के इरादे से, कॉमरेड शिवदास घोष ने 1948 में एक सही मार्क्सवादी क्रांतिकारी पार्टी के गठन की पहल की। इस देश के असंख्य छात्र-नौजवानों की तरह, वे पुनर्जागरण के विचारकों और क्रांतिकारियों के आदर्शों से प्रेरित थे और तत्कालीन क्रांतिकारिता से प्रेरित थे और एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के माता-पिता के आँसू की पृष्ठभूमि में, रखकर स्कूली जीवन से ही स्वदेशी आंदोलन में दिलो-जान से कूद पड़े थे। वे अत्यंत निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और आदर्शवान चरित्र के अधिकारी थे। उन्होंने मानव इतिहास के हर युग के महापुरुषों के चरित्र और जीवन-संघर्ष और स्वदेशी आंदोलन के सभी महान योद्धाओं से सीख ली थी। वे ज्ञान साधना की प्रबल चाह लेकर और सत्य की खोज का प्रण लेकर इस युग की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा मार्क्सवाद की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित हुए थे और मार्क्सवाद की शिक्षा के अनुसार, अपने स्वयं के विचारों, दृष्टिकोण, विभिन्न विषयों के विश्लेषण, जीवन-शैली, रूचि-संस्कृति, आचरण-व्यवहार को ढालने के कठिन संघर्ष के लिए समर्पित थे। जब उन्हें 1942 के अगस्त विद्रोह कें एक योद्धा के रूप में कैद किया गया, उस दौरान उन्होंने समझ लिया था कि सत्ता के हस्तांतरण के माध्यम से देश के गौरवशाली स्वतंत्रता आंदोलन के त्रासदीपूर्ण परिणाम होने वाले थे। वे समझ पाये थे कि अविभाजित सीपीआई के नेता, हालांकि, ईमानदार और त्यागी हैं, लेकिन मार्क्सवाद को ठीक से नहीं समझ पाने की वजह से पार्टी गठन की पद्धति, क्रांतिकारी नीतियों, रणनीति, रणकौशल और कार्य पद्धतिओं को तय करने में विफल रहे। संक्षेप में यूं कहें कि भारत की विशेष परिस्थिति के मुताबिक मार्क्सवाद को विशेष तौर पर प्रयोग करने के मामले में विफल हो गए थे, जिस काम को लेनिन ने रूस में और माओ त्से-तुंग ने चीन में किया था। इसलिए, अविभाजित सीपीआई को सर्वहारा पार्टी की बजाय शुरुआत से ही एक पेटी बुर्जुआ पार्टी के रूप में बनाया गया था। इसलिए, समग्र स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधीजी के नेतृत्व में क्रांति-विरोधी पूंजीपति वर्ग के हित में समझौतापरस्त धारा और नेताजी के नेतृत्व में मध्यम वर्गीय लोगों और आम लोगों के हित में गैर-समझौतावादी क्रांतिकारी धारा,के तीव्र द्वंद्व के बावजूद इस अविभाजित सीपीआई ने 1925 में स्टालिन द्वारा दी गई इस हिदायत को नहीं मान कर नेताजी के नेतृत्व का समर्थन करने की बजाय गांधीजी के नेतृत्व का समर्थन किया। सन् 1942 के जनउभार और आईएनए की लड़ाई का विरोध किया, देश के बंटवारे का समर्थन किया। इसके नतीजतन स्वतंत्रता आंदोलन में मध्यम वर्गीय परिवारों और आम लोगों के घरों के असंख्य युवक-युवतियों ने जान कुर्बान की, असीम बलिदान दिये, जेल गए, कालेपानी, देशनिकाले की सजाएं झेली, जबकि देशी पूंजीपतियों टाटा-बिड़ला- अंबानी-अडानी- मित्तल-जिंदलों में से किसी ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वे सर्वहारा वर्ग की सही मार्क्सवादी पार्टी नहीं होने का फायदा उठा कर सत्ता हथियाने जा रहे हैं।

इसलिए कॉमरेड शिवदास घोष ने देश में एक सही मार्क्सवादी पार्टी बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। उन दिनों उन्हें कोई नहीं जानता-पहचानता था। उन्होंने अपने चंद साथियों को साथ लेकर यह सफर शुरू किया। वे भी पूरी तरह अपरिचित थे। पैसा नहीं, सिर छिपाने का कोई ठौर-ठिकाना नहीं, उनकी रातें फुटपाथ पर कटीं, पार्क में, प्लेटफार्म पर बीतीं। दिन पर दिन भुखमरी का आलम था। उन दिनों ऑफिस का एक कमरा भी नहीं था। उस समय सिर्फ अविभाजित सीपीआई ही नहीं, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरसीपीआई - ये काफी बड़ी पार्टियां होती थी। उस स्थिति में एक पार्टी बनाना कितना मुश्किल था, लेकिन एक दृढ़ इरादे के साथ, उन्होंने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को औजार बना कर शुरुआत की थी। बहुतों ने उनका मजाक उड़ाया था। कइयों ने कहा था चमगिदड़ भी पक्षी है और एसयूसी भी पार्टी है। कहा था-यह कोई पार्टी है क्या, यह तो महज एक क्लब है। उस समय महान स्टालिन, माओ त्से-तुंग ने सीपीआई को मान्यता दी हुई थी। कॉमरेड शिवदास घोष का मजाक उड़ाते हुए इन पार्टियों ने कहा था, 'क्या आप स्टालिन-माओ त्से-तुंग से भी बड़े हैं?' उन्होंने उनका यह जवाब दिया था कि स्टालिन-माओ त्से-तुंग मेरे शिक्षक हैं। लेकिन आपने उनकी शिक्षाओं के अनुसार इस देश में पार्टी का निर्माण नहीं किया। मैंने उनकी शिक्षा को ठीक से लिया है और इसे लागू करके पार्टी बनाई है। उन्होंने गलती से आपका समर्थन कर दिया है क्योंकि वे भारत की स्थिति को नहीं जानते हैं। यही सही रास्ता है।

चौतरफा दुर्लघ्य प्रतिकूलता, अत्यधिक प्रतिरोध, इन सब से गुजरते हुए, वे आगे बढ़ते गए एक महान सपने को संजोकर, दुर्जेय संकल्प लेकर इन सब बाधाओं को पार कर गए। आप आज उन हालात की कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों के एक समूह ने उनके तर्क का समर्थन करते हुए कहा था, 'इतना बड़ा देश है, इतने बड़े-बड़े दल हैं, अनेक नामी-गिरामी नेता हैं, आपका न तो नाम है, न कोई जनशक्ति है, न ही कोई पैसा है, कोई प्रचार भी नहीं है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपका करियर बर्बाद हो जाएगा।' उन्होंने कहा था, मैं लड़ते-लड़ते मर जाऊंगा, मैं मरते-मरते भी लड़ूंगा, लेकिन जिसे मैंने सच माना है, उसको लेकर लड़ाई लड़ता जाऊंगा। मैं झूठ के सामने नतमस्तक होकर अपना विवेक नहीं बेच सकता। इसी तरह इस पार्टी का गठन हुआ। मैं, कॉमरेड माणिक मुखर्जी हम में से कुछ आज भी जीवित हैं, जो उस कठिन संघर्ष के साक्षी हैं, चश्मदीद गवाह हैं। उनकी राजनीतिक क्लास में, हम 20/25 लोग मौजूद होते थे, हाजरा पार्क में, जनसभा में 150-200 श्रोता उपस्थित होते थे, वे वक्ता होते थे, इतने से ही हम सोचते थे कि सभा बहुत सफल रही। हमारा परिचय क्या है? हमारी जितनी योग्यता, क्षमता, गुण आप देखते हैं, जिनकी वजह से आप प्यार करते हैं, शायद उसके लिए कुछ आदर-सम्मान भी करते हैं, ये सब हमको उनसे मिली हैं। हम उनके शिक्षण से लालित-पालित, प्रेरित हैं। नतीजतन, 5 अगस्त का यह दिन हमारे आंसुओं से जुड़ा है। मैं भी उनकी मृत्यु के समय उपस्थित था। अन्तिम बार वे सिर्फ हमारी तरफ देख रहे थे। अंतिम विदाई के इस क्षण में, इस उम्मीद के साथ (यहां रुलाई से कॉमरेड प्रभास घोष का गला रुंध जाता है; वे थोड़ी देर रुकते हैं) अवाक टकटकी लगाए नजर, लेकिन उम्मीद जता रहे थे कि हम झंडा लेकर चलेंगे। आज भी हम लड़ रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं। हमारी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है।

आज भारत में हमारे पास कई हजार कार्यकर्ता हैं। लाखों समर्थक हैं। हम 23 राज्यों में काम कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा, शक्ति का स्रोत क्या है? हमारी शक्ति का एकमात्र स्रोत है महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष के विचार। उन्होंने हमें सिखाया है कि लोग क्रांतिकारी आदर्शों, युक्ति-तर्क, सत्य के बल पर जीतेंगे। और प्यार, सौम्यता, उन्नत रूचि-संस्कृति के बल पर जीतेंगे। जहां भी आपको अन्याय-अत्याचार, जुल्म दिखाई देगा, आप उसके खिलाफ सिर उठाएंगे, लड़ेंगे। यह पार्टी चुनावी पार्टी नहीं है, यह पार्टी गद्दी पर काबिज होने की राजनीति नहीं करती है। यह पार्टी एक वर्ग संघर्ष, जन आंदोलन, लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। यही शिक्षा वे हमें दे गए हैं। हम इस शिक्षा के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि समाजवाद का पतन हो चुका है, यह बहुत दुखद घटना है। दुनिया की कई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टियाँ, जिनमें संघर्ष की लम्बी परम्पराएँ थीं, लेकिन आँख बंद करके रूस, चीन का अंधानुकरण करती थी, समाजवाद के पतन के बाद उनमें से कई भ्रमित हो गईं, खंडित-विखण्डित हो गईं, कमजोर हो गईं। लेकिन कॉमरेड शिवदास घोष ने मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ तुंग का कभी आँख बंद करके अनुसरण नहीं किया। उनकी शिक्षाओं को समझते हुए, उन्होंने मार्क्सवादी विज्ञान को द्वंद्वात्मक संबंधों के आधार पर आंका है। परिणामस्वरूप, एक छात्र के तौर पर उन्होंने स्टालिन का, माओ त्से-तुंग का सम्मान किया, और कुछ-कुछ मामलों में शिक्षक का आदर करते हुए ही, उनकी कुछ गलतियों पर भी चर्चा की।

इसलिए, मार्क्सवाद-लेनिनवाद को सही ढंग से अमल में लाने के आधार पर इस पार्टी का गठन होने के नतीजतन, विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में जहाँ अन्य पार्टियों का बेहद नुकसान हुआ है, वहीं हमारी पार्टी को लेकिन नुकसान नहीं उठाना पड़ा। हमें दु:ख हुआ, ठेस पहुंची, लेकिन हम निराश नहीं हुए। कॉमरेड शिवदास घोष ने हमें इस आपदा के लिए पहले से ही तैयार कर रखा था। इस मामले में, हमने कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं को औजार बनाकर एक मिसाल पेश की है - इस बात का मैं गर्व से दावा कर सकता हूं।

हम गर्व से दावा कर सकते हैं कि इस भयावह अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थिति में उनके दिखाये हुए रास्ते पर हम मार्क्सवाद-लेनिनवाद, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के महान झंडे को लेकर चल रहे हैं। हम जानते हैं कि दो ही रास्ते हैं। या तो पूंजीवाद-साम्राज्यवाद-फासीवाद को टिकाये रखना, जिसका अपरिहार्य परिणाम होगा जीवन के सर्वग्रासी संकट को बढ़ाकर मानव जीवन को और अधिक असहनीय बना डालना। नहीं तो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी क्रांति करनी चाहिए, मानव सभ्यता की रक्षा करनी चाहिए और इसे और भी ऊंचे सोपान पर ले जाना चाहिए

याद रखें, समाज वर्ग-विभाजित है, अमीर-गरीब, मालिक-मजदूर, शोषक-शोषित में बंटा हुआ है। राजनीति भी वर्ग-विभाजित है। पार्टी का नाम चाहे जो भी हो, झंडे के रंग, नारों में चाहे जो भी फर्क क्यों न हो, ये सब सरकारी पार्टियां ही पूंजीवाद के हित में, शोषण को बनाये रखने के हित में काम कर रही हैं और केवल हमारी पार्टी ही पूंजीवाद-विरोधी क्रान्तिकारी राजनीति का झंडा लेकर चल रही है।

लोगों को राजनीति को समझना होगा। प्रत्येक पार्टी के वर्ग चरित्र को समझना होगा, वरना वे अखबार-टीवी के प्रचार की हवा में बह कर, नेताओं के झूठे वादों से गुमराह होकर, धर्म-जाति-वर्ण विद्वेष के षड्यंत्रों में विभाजित होकर या पैसे के लालच में आकर कभी इस पार्टी को, कभी उस पार्टी को गद्दी में बैठाकर बार-बार ठगे जाएंगे। क्या यही लोग होते रहने देंगे? इसलिए राजनीति को समझना मुश्किल होते हुए भी, गांवों में, कस्बों-शहरों में, कल-कारखानों में, मलिन बस्तियों में, विभिन्न प्रतिष्ठानों में, अपनी खुद की जनकमेटियों की स्थापना करें, राजनीति का अभ्यास करें, किसी भी अन्याय-अत्याचार का मिलजुल कर विरोध करें, इन नेताओं से किसी भी समस्या को हल करने की भीख न मांगें। इज्जत के साथ सिर उठा कर जोरदार ढंग से मांग पूरी करवाने के लिए लड़ें। 'सभी पार्टियां समान हैं, सभी नेता धोखेबाज हैं'- इन बातों को कह कर हायतौबा करने का कोई लाभ नहीं होगा। इसका कारण ढूंढ़ें कि आप बार-बार क्यों ठगे गए हैं। पार्टियों की राजनीति और वर्ग चरित्र को जानें-समझें और इसे ठीक से समझने के लिए चाहिए सही राजनीतिक ज्ञान, जो केवल मार्क्सवाद-लेनिनवाद -शिवदास घोष चिंतन ही दे सकता है। इसके अलावा चाहिए उन्नत चरित्र, नैतिक बल, इन्सानियत। इसके लिए, किसी को पहले नवजागरण के मनीषियों, स्वदेशी आंदोलन के क्रांतिकारी शहीदों के क्रांतिकारी चरित्र से सीखना चाहिए, और फिर एक कदम आगे जाकर सर्वहारा उन्नत संस्कृति हासिल करनी होगी। इस तरह का संघर्ष करते हुए कदम-कदम आगे बढ़ते हुए समाजवादी क्रांति की तैयारी करनी होगी। एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) को मजबूत करने की जरूरत है। सोच कर देखिए, बड़ी-बड़ी पार्टियां, शत्रु वर्ग की प्रतिनिधि कितना नुकसान पहुंचा रही हैं,, सर्वनाश कर रही हैं - उनके पीछे दौड़ेंगे, या तुलना में भले ही छोटी पार्टी आपके हितों के लिए लड़ रही है, गरीबों के हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत है, क्रांतिकारी आदर्शों, नीति-सिद्धांतों व चरित्र को लेकर चल रही है, वोटों के लोभ-लालच में, गद्दी पर बैठने के लोभ में खुद को बेच नहीं दिया है, उसको मजबूत करेंगे? इस प्रश्न के समाधान पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात यहां समाप्त कर रहा हूं।

इंकलाब जिंदाबाद!

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जिंदाबाद!

सर्वहारा वर्ग के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष लाल सलाम!

स्रोत: (1) कलाकार का नवजन्म: रोमां रोलां (2) लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र - रचनाएँ राममोहन राय रचनावली (3) विद्यासागर रचना संग्रह (4) शरत ग्रंथावली (5), (15), (17) और (19) वाणी ओ रचना - विवेकानंद (6) बंच ऑफ थोट: एमएस गोलवलकर (7) वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड: एमएस गोलवलकर (8) आनंदबाजार पत्रिका, 14 मई, 1940 (9) सुभाष रचनावली, खण्ड 4 (10) वही, खण्ड 2 (11) वह, खण्ड 4 (12) कालांतर, हिंदू-मुस्लिम (13) और (14) अज्ञात निबंध - संपूर्ण लेख, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय (16) शिकागो भाषण

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com** **फोन नं. : 011-25726631, 9868350503**